प्रेरणा स्रोत
स्व. श्री यशवंतजी घोड़ावत

RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ...सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

स्वार्थ हर तरह की भाषा बोलता है, हर तरह की भूमिका अदा करता है, यहां तक कि निःस्वार्थता की भाषा भी नहीं छोड़ता।

रामधारी सिंह दिनकर

वर्ष-06, अंक - 40 (साप्ताहिक) खवासा, गुरुवार 27 जून 2024 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

शराब मामला: अरविंद केजरीवाल को झटका,

कोर्ट ने दी सीबीआई को 3 दिन की रिमांड

नई दिल्ली।

दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यूस्थित विशेष अदालत ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। अवकाशकालीन विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत न`मामले में केजरीवाल की पांच दिन की सीबीआई की हिरासत की याचिका पर संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने केजरीवाल की हिरासत की मांग की थी।

अदालत ने फैसले में कहा

सीबीआई के आवेदन को तीन दिन के लिए अनुमति दी जाती है। केजरीवाल को बुधवार को तिहाड़ जेल सेकड़ी सुरक्षा में अदालत मेंपेश किया गया। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार करने की अर्जी दी। इसे अदालत ने मंजूर कर लिया। केजरीवाल ने अदालत के समक्ष दावा किया कि वह इस मामले में निर्दोष हैं। सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने अदालत से कहा कि सीबीआई सूत्रों के हवाले से मीडिया में दिखाया जा रहा है कि मैंनेपूरा दो मनीष सिसोदिया पर डाल दिया है। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि सिसोदिया दोषी हैं या कोई और दोषी है। मैंने कहा है कि सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के साथ मैं भी निर्दोष हूं। केजरीवाल नेयह भी आरोप लगाया कि सीबीआई इस मामले को सनसनी खेज बना रही है

केजरीवाल से पूछताछ जरूरी है। इस मामले में केजरीवाल का सबूतों और मामले के अन्य आरोपियों से आमना-सामना कराए जाने की जरूरत है सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआई से यह भी पूछ लिया कि केजरीवाल को अब गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। इस पर सीबीआई के वकील ने कहा कि एजेंसी नेचुनाव के दौरान ऐसा करने से परहेज किया। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर अदालत मेंभी मामला लंबित था। चुनाव के दौरान एजेंसी का यह संयम दर्शाता है कि उन्हें तब गिरफ्तार नहीं किया गया जब वह चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। वहीं केजरीवाल के वकील ने सीबीआई की हिरासत लेने की अर्जी को संदिग्ध करार दिया। उन्होंने कहा कि बेवजह द्वेषपूर्ण आरोप लगाए जा रहे हैं। यह शक्ति के दुरुपयोग है। इससे पहले केजरीवाल ने विशेष अदालत की ओर से 20 जून को दी गई जमानत के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट की 21 जून के अंतरिम रोक के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में वापस लेली। केजरीवाल की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट ने चूंकि विस्तृत आदेश पारित किया है इसलिए हम ठोस अपील दाखिल करेंगे।

अध्यक्ष बने रहेंगे वीडी शर्मा

भोपाल।

केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर मध्य प्रदेश में लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड तो कायम है लेकिन ऐसी ही एक स्क्रिप्ट भाजपा संगठन में तैयार हुई है । जी हां , हम बात कर रहे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा की। विष्णु दत्त शर्मा लगातार 4 साल से अधिक प्रदेश अध्यक्ष बने रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। इससे पहले लगातार अध्यक्ष बने रहने का रिकॉर्ड भाजपा खेमे में किसी के नाम पर नहीं है । राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नए वर्ष मतलब 2025 में मिलेगा लेकिन उसके पहले कार्यवाहक अध्यक्ष चुना जाता है, तो ऐसा माना जा रहा है की वही पूर्णकालिक अध्यक्ष बन सकता है। ऐसा पिछला उदाहरण देखें तो समझ में आएगा ।

राजनीतिक पंडित मानते हैं की राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए अमित शाह जब मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री बने थे तब जेपी नड्डा को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था और उसके बाद उन्हें ही पूर्ण कालिक अध्यक्ष घोषित कर दिया था । इसी कारण ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा संगठन कार्यवाहक अध्यक्ष जल्द ही घोषित कर देगा और उसने बाद से जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हट जाएंगे।

भारतीय जनता पार्टी में संगठन चुनाव को लेकर खाता लगभग तैयार कर लिया है इसकी शुरुआत सदस्यता अभियान से होगी और चरणबद्ध तरीके से दिसंबर के अंत तक भाजपा को पूर्ण कालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है । अगर भाजपा के कार्यक्रम को समझे तो सबसे पहले 1 अगस्त से भाजपा का सदस्यता अभियान 15 सितंबर तक चलेगा। उसके बाद सक्रिय सदस्यता अभियान 15 से 30 सितंबर तक होगा। उसके बाद एक अक्तूबर से सदस्यता सत्यापन किया जाएगा। फिर एक से 15 नवंबर के बीच में मंडल अध्यक्षों का चुनाव किया जाएगा। इसके बाद 16 से 30 नवंबर के बीच जिला अध्यक्षों का चुनाव होगा और एक से 15 दिसंबर के बीच में सभी प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्षों की तैनाती और राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य का चुनाव होगा । उसके बाद 15 दिसंबर के आस पास राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा।

लोकसभा स्पीकर के चुनाव में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिखाई ताकत

नई दिल्ली, एजेंसी।

18वीं राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत से ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नए तेवर में दिखाई दे रहे हैं। आम चुनाव में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन का श्रेय राहुल गांधी को मिल रहा है।

कांग्रेस में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी की सदन में परख किस तरह बढ़ाई गई, इसकी एक बंदी बुधवार को चुनाव के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सामने आई। जयशंकर बिड़ला को कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सत्ताधारी एनडीए गठबंधन ने स्पीकर पद के लिए ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव आम लोगों से चुनने की अपील की। पीएम मोदी के प्रस्ताव के बाद विपक्षी उम्मीदवार के.सुरेश ने नाम वापस ले लिया। इसके बाद बिड़ला फिर से निर्विरोध कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद संसदीय परंपरा के अनुसार, कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष बिरला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आसन तक ले गए। इस दौरान लोकसभा में जो दृश्य दिखा, उससे राहुल गांधी की बढ़ती हुई ताकत को दिखाया गया है। जब पीएम मोदी बिड़ला को मंच पर खड़ा किया गया, तब विपक्षी नेता भी उनके साथ ही मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव में स्पीकर बिरला से हाथ मिलाकर सबसे पहले भाषण दिया। इस बीच राहुल गांधी भी वहां मौजूद हैं, तब पीएम मोदी उन्हें भी आगे आने का संकेत देते हैं। इसके बाद राहुल गांधी बिरला से हाथ मिलाते हैं और फिर वे उनके साथ लेकर स्पीकर के आसन तक ले जाते हैं। इस दौरान संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू उनके पीछे-पीछे चल रहे थे। इसके बाद कांग्रेस में स्पीकर के आसन पर पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने एक बार फिर बिरला को शुभकामनाएं दीं। फिर राहुल गांधी ने भी नए स्पीकर को शुभकामनाएं दीं और इसके बाद केंद्रीय मंत्री रीजीजू ने भी बिरला से हाथ मिलाया।

म्यांमार विदेश मंत्री से मिले जयशंकर, हिंसा पर जताई चिंता

नई दिल्ली।

म्यामांर में भारतीय सीमा से सटे क्षेत्रों में लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रहीं हैं। ऐसे में वहां मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भारत भी चिंतित है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने म्यांमार के अपने समकक्ष यू थान श्वे के साथ मुलाकात की। इस दौरान भारत ने म्यांमार में भारतीय सीमा के पास जारी हिंसा पर चिंता व्यक्त की। एस जयशंकर ने म्यामांर के विदेश मंत्री से म्यावाडे शहर में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने में सहयोग करने की भी मांग की।

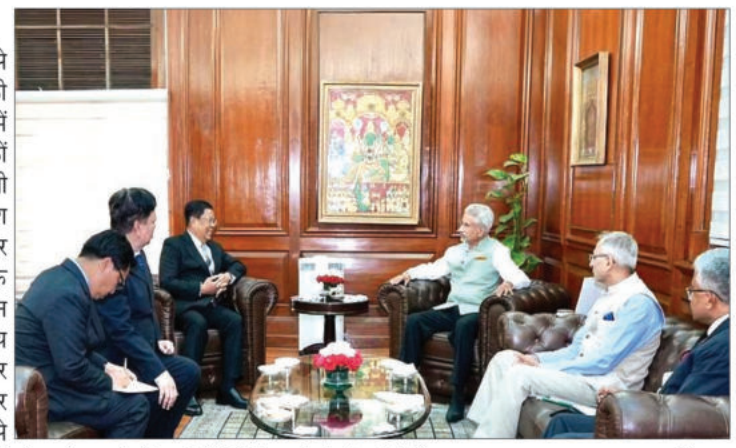

भारत के विदेश मंत्री ने म्यांमार के उप प्रधानमंत्री के साथ भी मुलाकात की। सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा की गए एक पोस्ट में लिखा गया है कि बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने म्यांमार में चल रही भारत की परियोजनाओं को सुरक्षा प्रदान करने पर जोर दिया। जयशंकर ने खासतौर पर भारत-म्यांमार सीमा के पास लगातार हो रही हिंसा पर चिंता जताई।

ता दें कि म्यांमार के कई क्षेत्रों में सेना (जुंटा) और विद्रोहियों के बीच जंग जारी है। म्यांमार में विद्रोहियों ने पहले से ही कई क्षेत्रों पर अपना कब्जा किया हुआ है। अप्रैल के महीने में विद्रोहियों ने जुंटा के सैन्य अड्डे और म्यावाडी स्थित कमान केंद्र पर कब्जा कर लिया था।

सभी पक्षों से बात करने को तैयार भारत

बैठक में जयशंकर ने म्यांमार के समकक्ष से कहा कि भारत, म्यामांर में हिंसा की स्थिति से निपटने के लिए सभी पक्षों से बातचीत करने के लिए तैयार है। भारत के विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा 'म्यांमार के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात की। मुलाकात में भारत-म्यांमार सीमा के पास बढ़ती हिंसा पर चिंता जताई गई। भारत इस मामले में सभी पक्षों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। म्यांमार में चल रही भारत की परियोजनाओं को सुरक्षा प्रदान करने पर जोर दिया गया। साथ ही वहां फंसे भारतीय लोगों की स्वदेश वापसी में मदद प्रदान करने का अनुरोध किया गया।'

म्यांमार में यह हालात

1 फरवरी, 2021 को म्यांमार में तख्तापलट हुआ था और सेना द्वारा सत्ता पर कब्जा कर लिया गया। इसके बाद से म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली की मांग को लेकर व्यापक हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। म्यांमार के रखाइन राज्य के अलावा अन्य क्षेत्रों में बीते वर्ष अक्टूबर से सशस्त्र जातीय समूहों और सेना के बीच भीषण लड़ाई हो रही है। पिछले वर्ष नवंबर के महीने में भारत-म्यांमार की सीमा से सटे कई प्रमुख शहरों में हिंसा और अधिक बढ़ गई थी। इस वजह से भारत द्वारा मणिपुर और मिजोरम की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई गई है।

यात्रियों के कान से निकला खून

सियोल एजेंसी।

दक्षिण कोरिया से ताइवान जाने वाली बोइंग की फ्लाइट केई189 उड़ान भरने के कुछ देर बाद अचानक 26,900 फीट नीचे आ गई, जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इस दौरान कई यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत हुई और कान में दर्द हुआ। इसके बाद फ्लाइट के क्रू मेंबर्स ने यात्रियों को ऑक्सीजन मास्क लगाने को कहा।

फ्लाइट ने शनिवार को स्थानीय समयानुसार शाम 4 बजकर 45 मिनट पर दक्षिण कोरिया के इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। उड़ान के 50 मिनट बाद ही उसमें तकनीकी खराबी आ गई। इसके कारण फ्लाइट 15 मिनट में ही 26,900 फीट नीचे आ गई। उस समय यह दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप के ऊपर थी। तब विमान के प्रेशर सिस्टम ने तकनीकी खराबी का सिग्नल दिया, जिसके बाद फ्लाइट को टेकऑफ की लोकेशन इंचियोन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारा गया।

15 यात्रियों के कान में दर्द

फ्लाइट की ऊंचाई अचानक कम होने की वजह से घायल हुए 17 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि उन्हें कुछ समय बाद ही डिस्चार्ज कर दिया गया था। वहीं 15 यात्रियों ने कान के परदे में दर्द या हाइपरवेंटिलेशन की शिकायत की। यात्रियों ने बताया कि वे लोग बहुत डर गए थे और विमान में मौजूद बच्चे रोने लगे थे। यात्रियों को डर था कि कहीं फ्लाइट नीचे न गिर जाए। कोरियन एविएशन अथॉरिटी ने फ्लाइट की तकनीकी खराबी का कारण जानने के लिए जांच के आदेश दे दिए है। सभी यात्रियों को 19 घंटे बाद एक दूसरी फ्लाइट से ताइवान के ताइपे पहुंचा गया।

मैं हर मोर्चे पर कांग्रेस के साथ : ममता

नई दिल्ली एजेंसी।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, अब एक परिपक्व नेता और कुशल समन्वयक के तौर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करके मतदाता को पार्टी से जोड़ने में कामयाबी हासिल की, तो एक कुशल रणनीतिकार होने का प्रमाण भी दिया। इसके अलावा दलों और नेताओं को एकजुट करने में भी राहुल गांधी सफल हो रहे हैं। इसकी बानगी आज बुधवार को हुए लोकसभा के स्पीकर चुनाव में देखने को मिली। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कांग्रेस से खफा थीं। उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी थी। पार्टी के दूसरे नेताओं का मानना था कि दीदी को मना पाना इतना आसान नहीं है। कोई उनसे बात करने को भी तैयार नहीं था, उन्हें लग रहा था कि दीदी नहीं मानीं तो पूरे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। इसके बाद खुद राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला और सीएम ममता बनर्जी से फोन पर आधा घंटे बात की। बताया गया कि दीदी राहुल गांधी की हर एक बात से सहमत हो गईं। उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि टीएमसी हर एक मोर्चे पर कांग्रेस के साथ खड़ी है।

18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र में ही विपक्षी गठबंधन में तकरार दिखने लगी थी। स्पीकर पद के लिए इंडिया अलांयस ने के. सुरेश को मैदान में उतारकर मोदी सरकार को चुनौती दी थी। कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया अलायंस एनडीए को मात देने की पूरी कोशिश में था। इंडिया अलायंस के कैंडिडेट के सुरेश को विपक्षी सांसदों का साथ मिले, इसके लिए कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ी। यही वजह है कि जैसे ही कांग्रेस को ममता की नाराजगी की खबर लगी, तुरंत राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल लिया। राहुल गांधी ने आनन-फानन में ममता बनर्जी को फोन घुमाया और करीब 30 मिनट तक बातचीत करके उन्हें मना लिया। दरअसल, मंगलवार को कांग्रेस ने के. सुरेश को स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया था। आनन-फानन में इंडिया अलायंस का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद ममता बनर्जी की टीएमसी कांग्रेस से खफा हो गई। टीएमसी ने आरोप लगाया कि विपक्ष के स्पीकर कैंडिडेट को लेकर उससे राय नहीं ली गई। यही वजह है कि टीएमसी ने समर्थन पत्र पर साइन नहीं किया था। टीएमसी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने अपनी मर्जी से के. सुरेश को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया।

राहुल गांधी ने तुरंत ममता बनर्जी को फोन किया। राहुल गांधी और ममता बनर्जी के बीच करीब आधे घंटे तक फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत के दौरान स्पीकर के चुनाव को लेकर भी बातचीत हुई। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी ने के. सुरेश के नामांकन के बारे में पहले न बताने के लिए टीएमसी से माफी मांगी। इसके बाद ममता बनर्जी मान गईं और इंडिया ब्लॉक की बैठक में टीएमसी के 2 सीनियर नेताओं को भेजने का फैसला किया। इससे पहले राहुल गांधी ने लोकसभा में अभिषेक बनर्जी से भी चर्चा की थी। इसके बाद ममता ने फैसला लिया है कि टीएमसी इंडिया अलायंस के कैंडिडेट के सुरेश का समर्थन करेगी।

सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी के फोन के बाद ही ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खरगे के घर पर हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में टीएमसी नेताओं को भेजा। हालांकि, टीएमसी ने कांग्रेस से साफ कहा कि वो बेहतर समन्वय और संवाद की अपेक्षा करती है। टीएमसी इस बात से नाराज है कि लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर के सुरेश के नामांकन से पहले कांग्रेस ने उससे बात नहीं की। अभिषेक बनर्जी ने खुलकर कांग्रेस के फैसले को एकतरफा बता दिया था। इसके बाद राहुल ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। टीएमसी सूत्रों का मानना है कि ममता बनर्जी संसदीय परंपराओं में विश्वास करती हैं।

अमरनाथ यात्रा पर आतंकवादी साया, चप्पे-चप्पे पर नजर

जम्मू, एजेंसी।

अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के पास ऐसे पुष्ठ मिल रहे हैं कि इस बार खतरनाक यात्रा में खल्लाल डाला जा सकता है। हमले होने के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक कर कहा था कि यात्रा में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए और यात्रा को सर्वोत्तम संभव बनाने का जिम्मा सुरक्षा बलों को दिया जाना चाहिए। यही कारण है कि सुरक्षा में किसी प्रकार की ढील नहीं बरती जा रही है। आधार शिविर भगवती नगर से 28 तारीख को पहले जत्था रवाना होगा और 29 तारीख को बाबा बर्फानी की यात्रा की शुरुआत होगी। इस तरह इस यात्रा पर आतंकवादी साया बना हुआ है जिसे देखते हुए सुरक्षा बल किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतना चाहते। यही वजह है कि भगवती नगर आधार शिविर के आसपास हर जगह मेटल डिटेक्टर से हर एक चप्पे-चप्पे को खंगाल रहा है। वहीं डॉग स्क्वायड टीम भी आसपास के इलाकों को पूरी तरह से जांच कर रही है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा से पहले रियासी में श्री माता वैष्णो देवी के भक्तों की बस पर हमला किया गया था। उसके बाद हीरानगर में ब्यूरो से जुड़ी हुई। फिर जम्मू-कश्मीर ने ही डोडा के अंदर दोबारा हमला किया।

फर्जी दस्तावेज बनाकर रजिस्ट्री करवाने का मामला पहुंचा कलेक्टर के पास

तहसीलदार को जांच के आदेश, अजजा वर्ग की जमीनें हतियाने के लिए लोग अपना रहे नए नए हथकंडे

माही की गूंज, झाबुआ।

इन दिनों जिले में ऐसे मामले सामने आ रहे है जहां अजजा वर्ग की भूमि जो कि आदिवासी जिला होने के कारण जमीन अन्य वर्ग द्वारा नहीं खरीदी जा सकती का नियम लागू है, लेकिन लोग नए-नए हथकंडे लगा कर आदिवासियों की जमीन अपने नाम करवा रहे है। हालांकि की जमीन की रजिस्ट्री से पूर्व जांच के कई तरह के नियम बने हुए है, लेकिन चंद पैसों की लालच में सारे नियम कायदे ताक में रख कर रजिस्ट्री करवा दी जाती है। ऐसा ही एक मामला जिले के अमरगढ़ क्षेत्र में सामने आया है। जहां के शिकायतकर्ता ने जनसुनवाई में आवेदन देते हुए उसकी जमीन की रजिस्ट्री फर्जी दस्तावेजों के साथ होने की शिकायत दर्ज करवाई है। जिला कलेक्टर ने मामले की सुनवाई तहसीलदार पेटलावद को सौंपी है।

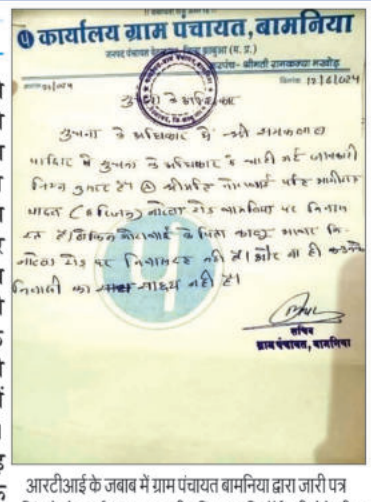
कार्यालय ग्राम पंचायत, बामनिया

आरटीआई के जबाब में ग्राम पंचायत बामनिया द्वारा जारी पत्र जिंसमे गौराबाई भाभर नाम की महिला का रिकॉर्ड नही होने की पुष्टि की गई।

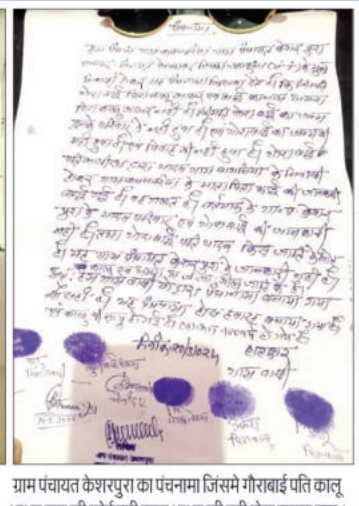
ग्राम पंचायत केशरपुरा का पंचनामा जिंसमे गौराबाई पति कालू भाभर नाम की कोई पुत्री कालू भाभर की नही होना बताया गया।

आधार कार्ड में गौराबाई पिता कालू भाभर नाम दर्ज।

समग्र आईडी में गौराबाई यादव नाम दर्ज।

फर्जी दस्तावेजों के साथ की गई रजिस्ट्री

शिकायतकर्ता कैलाश पिता रूपसिंह और रूपसिंह पिता धन्ना निवासी ग्वालटोली अमरगढ़ विकास खण्ड पेटलावद ने जनसुनवाई में कलेक्टर को आवेदन देते हुए बताया कि गौराबाई पति भगीरथ यादव निवासी बामनिया जो कि अजा वर्ग में आती है। गौराबाई के पति भागीरथ यादव ने खुद अपनी पत्नी का ग्राम कचनारिया ग्राम पंचायत केशरपुरा निवासी कालू भाभर को पिता और अमरा भाभर को भाई बता कर मेरे पिता की ग्राम रामपुरिया-अमरगढ़ की जमीन धोखाधड़ी कर खरीद कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर रजिस्ट्री करवा ली। जबकि मध्यप्रदेश भू राजस्व सहिंता की धारा 165 (6) अनुसार कोई भी गैर आदिवासी व्यक्ति आदिवासी की भूमि नहीं खरीद सकता। हमें इसकी जानकारी मिली कि मेरे पिता से धोखाधड़ी कर गैर जाती के व्यक्ति ने जमीन खरीद ली है।

पूर्व में भी रजिस्ट्री शून्य करने के लिए दिया जा चुका है आवेदन

शिकायतकर्ता के अनुसार रजिस्ट्री को शुन्य की कार्यवाही हेतु पूर्व में कलेक्टर को आवेदन दिया जा चुका है जो कि जनसुनवाई क्रमांक 50490 दिनांक 03/03/2020 को दस्तावेज बनाकर भूमि के फर्जी तरिके से आदिवासी (अ.ज.जा) बनकर फर्जी तरीके से खरीदकर कब्जे में ले लिया था। लेकिन महिला का पति भागीरथ यादव जो कि शिकायती व्यक्ति है अधिकारियों की अन्य मामलों में शिकायत कर उन पर दबाव बना कर मामला मिलकर सेट कर लिया था। शिकायतकर्ता ने मामले की उच्चस्तरीय जांच करवा कर, भा.द.स. के अन्तर्गत एफ.आई-आर- करवा कर न्याय से विधिवत रूप से रजिस्ट्री शुन्य कर जमीन वापस दिलवाने की मांग की है।

सूचना अधिकार में मिली जानकारी में हुआ खुलासा

गौराबाई के आधार कार्ड में उनका नाम गौराबाई पिता कालू भाभर दर्ज है और निवास का स्थान नारेला रोड बामनिया बताया गया। जब इस कि जानकारी झमकलाल पाटीदार नाम के व्यक्ति ने ग्राम पंचायत बामनिया से मांगी तो ग्राम पंचायत की ओर से लिखित जवाब दिया गया कि इस नाम की कोई महिला इस पते पर निवासरत नहीं है, न ही इसका कोई साक्ष्य ग्राम पंचायत के पास रिकॉर्ड अनुसार उपलब्ध है। इतना ही नहीं एक पंचनामा भी गूंज के पास आया है, जिसमें ग्राम पंचायत केशरपुरा के सचिव सहित ग्रामीणों एवं कालू भाभर के परिवार के हस्ताक्षर ओर अंगूठा निशानियां है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि गौराबाई नाम की किसी लड़की का जन्म कालू भाभर के परिवार में नहीं हुआ है। बामनिया निवासी भगीरथ यादव द्वारा जो उनकी पत्नी के माता-पिता, भाई की जो जानकारी केशरपुरा पंचायत की होना बताई है वो बिल्कुल गलत है। इस प्रकार के प्रमाण के बाद भी क्या जांच दल इन सब दस्तावेजों को खंगाल कर इनकीं पुष्टि कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा या फिर वर्ष 2020 की शिकायत की तरह इस शिकायत को भी रफा -दफा कर दिया जाएगा ये देखना होगा।

सरकारी जमीन को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े

दोनों पक्षों में हुई हाथा पाई, मामला पुलिस तक भी पहुंचा

माही की गूंज
भामल/खवासा

ग्राम भामल में सरकारी जमीन को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। जिसमें दोनों की आमने-सामने हाथा-पाई भी हुई है। बताते हैं बारिश का सीजन है और किसान द्वारा इन दिनों बोवनी का कार्य किया जा रहा है। हमेशा इसी समय पर सबसे ज्यादा विवाद जमीन को लेकर ही होते हैं।

बुधवार को भी सुबह 11 से 12 बजे के मध्य ऐसा ही मामले भामल में सामने आया। जहां दो पक्ष में आपस में मारपीट तक हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दशरथ जादव अपने खेत पर बोवनी कर रहे था, तो दूसरे पक्ष से मांगू सिंह चौहान एवं उसके घर के सदस्य पहुंचे कहने लगे कि जहां तुम बोवनी कर रहे हो यह जमीन मेरी है, आइंदा इस जमीन पर बोवनी नहीं करना, नहीं तो आपके और हमारे झगड़े होंगे। उसके बाद दोनों पक्ष की आपस में मारपीट शुरू हो गई। दशरथ जादव का कहना है कि मेरे खेत के पास ही सरकारी जमीन है और में काफी वर्षो से इस पर फ़सल बो रहा हूं। जबकि मैं लगातार सरकारी जमीन की रसीद भी कटवा रहा हूं, लेकिन जबरदस्ती मांगू सिंह चौहान आकर हमसे झगड़ा कर रहे हैं। साथ ही हमें गाली गलौज के साथ मारपीट पर उतारू हो गए एवं मेरी पत्नी बदरी से भी हाथापाई की। उसके कपड़े आदि फाड़ दिए। जबकि मांगूसिंह चौहान का इस जमीन से कोई लेना-देना नहीं है और वह हमसे पर जबरदस्ती जमीन लेने पर उतारू हो रहे हैं। हम कभी भी यह जमीन उनको नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं मांगूसिंह चौहान का कहना है कि मेरा रास्ता भी उसी खेत के समीप से है और मेरा खेत भी नजदीक है। यह सरकारी जमीन मेरी ही है और मैं ही इस पर बोवनी करूँगा। बहसबाजी के साथ ही दोनों पक्षों में जमीन को लेकर मारपीट शुरू हो गई। आसपास खेत पर कार्य कर रहे ग्रामीणों ने दोनों पक्षों को छुड़वाया। गांव में यह सरकारी जमीन चर्चा का विषय बनी हुई है। विवाद के बाद दोनों पक्षों ने खवासा चौकी पहुंचकर एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज करवाया।

स्कूल बस पर हुई कार्यवाही

माही की गूंज, धार। मोटर यान अधिनियम की विभिन्न धाराओं में कार्यवाही कर वाहनों में क्षमता से ज्यादा सवारी ढोने वालों पर की गई। साथ ही 15 से अधिक स्कूल बसों की विशेष चेकिंग करने पर एक स्कूल बस बिना वैध दस्तावेज के संचालित पाए जाने पर उसे जब्त की गई।

खेत में बने मकान से 200 पेटी मदिरा जप्त

माही की गूंज, बड़नगर। बड़नगर आबकारी प्रभारी उप निरीक्षक वंदना मोरी ने ग्राम बडगारा के खेत में बने रहवासी मकान से अवैध रूप से संग्रहित 200 पेटी मदिरा जप्त करने में सफलता हासिल की। आरोपी घनश्याम पिता पन्नालाल जायसवाल से एक हजार 822 बल्क लीटर मदिरा जिसका अनुमानित मूल्य 9 लाख 27 हजार 260 रुपए है जप्त कर, आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया। आबकारी उप निरीक्षक वंदना मोरी की टीम में आबकारी मुख्य आरक्षक प्रेमचंद जटिया आरक्षक अनिल मंदेरिया, आदित्य राज नागर, ज्योति आदि का योगदान रहा।

पहले चरण में 10 करोड़ से अधिक की लागत से मंगलनाथ मंदिर परिसर में किया जाएगा स्टोन क्लैडिंग का काम

माही की गूंज, उज्जैन।

उज्जैन सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के अंतर्गत पहले चरण में 10 करोड़ से अधिक की लागत से मंगलनाथ मंदिर परिसर में स्टोन क्लैडिंग का काम किया जाएगा।

कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बुधवार सुबह मंगलनाथ मंदिर पहुंचकर यहां प्रस्तावित निर्माण कार्यों के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने सिंहस्थ 2028 के लिए मंदिर परिसर के कायाकल्प के लिए प्रस्तवतित 20 करोड राशि से प्रस्तावितकार्यो डीपीआर का अवलोकन किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सीईओ उज्जैन विकास प्राधिकरण संदीप सोनी, अधीक्षण यंत्री नीरज पांडे, एसडीएम एलएन गर्ग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहें।

मंगलनाथ मंदिर के कायाकल्प के पहले चरण में 10.78 करोड़ की लागत से स्टोन क्लैडिंग कार्य किया जाएगा, जिसमें इंटरनल कॉलम्स, शिखर, डोम, एक्सटीरियर फसाड् तथा वर्तमान स्टोन क्लीनिंग कार्य की मरम्मत की जाएगी। कलेक्टर श्री सिंह ने निर्माण एजेंसी उज्जैन विकास प्राधिकरण को इन कार्यों की स्वीकृति संबंधी आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने दूसरे चरण के प्रस्तावित कार्यों के संबंध में भी अधिकारियों से चर्चा की।

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न

माही की गूंज, शाजापुर।

कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना की अध्यक्षता में आज मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर सुश्री बाफना ने विभागीय योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगतिरत कार्यों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शाजापुर के अंतर्गत ब्रिज निर्माण कार्यों, संधारण एवं रखरखाव के अंतर्गत मार्गों की जानकारी प्राप्त की।

इस दौरान कलेक्टर ने महाप्रबंधक संजय श्रीवास्तव को निर्देश दिये कि प्रगतिरत कार्यों को निर्धारित समय अवधि में पूर्ण कराएं। साथ ही उन्होंने फिल्ड भ्रमण कर खराब हो रही सड़कों को संबंधित ठेकेदार के माध्यम से सुधरवाने के निर्देश दिये। इस दौरान उन्होंने कालापीपल क्षेत्र अंतर्गत आने वाली सड़कों के सोल्डर, गड्ढे को रिपेयर करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने महाप्रबंधक को निर्देश दिये कि विभाग अंतर्गत आने वाले मार्गों के पुल-पुलिया पर संकेतक बोर्ड लगवाएं। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि वर्षाकाल के दौरान जनहानि न हो, इसके लिए अभी से जीर्ण-शीर्ण पुल-पुलियाओं का चिन्हांकन कर उनकी मरम्मत आदि कार्य कराना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री संतोष टैगोर, सहायक प्रबंधक एवं उपयंत्री मौजूद थे।

वे बच्चे जो कभी घर नहीं लौट पाते

हाल ही में दिल्ली पुलिस ने चौदह साल से कम उम्र के तेईस खोए हुए बच्चों को उनके माता-पिता से मिलवाया है। पुलिस ने बच्चों की काउंसलिंग भी की। पता चला कि वे घर का रास्ता भटककर खो गए थे। इनमें से कई बच्चे घर से बाहर खेलने के लिए गए थे। कई दुकानों से सामान लाने गए थे और रास्ता भूल गए थे। कई बच्चे ऐसे भी थे जो ठीक से बोल नहीं पाते थे। पुलिस ने बताया कि इन बच्चों को अपने घर का पता नहीं मालूम था। न ही वे ये बता सकते थे कि उनके घर के आसपास ऐसी कौन-सी मशहूर जगह या लैंडमार्क है जहां पहुंचकर घर जाया जा सके। पुलिस को पता चला कि घर वालों ने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया था कि बच्चों को घर का पता याद होना जरूरी है।

अब पुलिस माता-पिता को इस बारे में शिक्षित कर रही है कि वे बच्चों को अपने घर का पता, टेलीफोन नम्बर आदि जरूर याद कराएं। उनके कपड़ों में घर का पता और फोन नम्बर लिखकर हमेशा रख दें जिससे अगर वे रास्ता भूल भी जाएं तो कोई उन्हें घर पहुंचा दे। पुलिस के पास आएं तो पुलिस को भी बच्चों को घर लाने में आसानी हो। दिल्ली पुलिस ने ऐसे सोलह बच्चों को भी ढूंढ़ निकाला जिन पर इनाम घोषित था। पैंतालीस ऐसे बच्चों को भी उनके घर पहुंचाया गया, जो परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाते थे, इस वजह से घर वालों की डांट खाते थे। इसलिए वे बिना बताए घर से चले गए थे।

बच्चों का खोना या हाट, मेले में घर वालों से बिछुड़ना कोई नई बात नहीं है। इस विषय पर बहुत-सी फिल्में भी बन चुकी हैं। बचपन में इसीलिए अक्सर घर वाले घर से बाहर तभी जाने देते थे, जब घर का कोई बड़ा साथ हो। दरअसल, बच्चे चुराने वाले गिरोह भी सक्रिय रहते थे, जो आज भी रहते हैं। इसके अलावा अड़ोस-पड़ोस भी आज की तरह कोई बेगाना नहीं था। हर कोई एक-दूसरे के परिवार वालों को जानता था, इसलिए बच्चे सुरक्षित भी रहते थे।

बचपन बचाओ आंदोलन की रिपोर्ट 'मिसिंग चिल्ड्रन आफ इंडिया' के अनुसार अपने देश में हर साल छियानवे हजार बच्चे खो जाते हैं, जिनमें से इकतालीस हजार, पांच सौ छियालीस बच्चे कभी नहीं मिलते। संगठन का कहना है कि भारत में हर घंटे ग्यारह बच्चे खो जाते हैं। इनमें से चार का पता कभी नहीं चलता।

भारत के छह सौ चालीस जिलों में से तीन सौ बानवे जिलों में जनवरी, 2008 से जनवरी, 2010 में खोए हुए बच्चों का अध्ययन किया गया था। उसी के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई थी। इसमें सबसे गम्भीर बात यह बताई गई थी कि खोए हुए बच्चे या तो बंधुआ मजदूरी का काम करते हैं या तरह-तरह से उनका यौन शोषण किया जाता है। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से सबसे ज्यादा बच्चे खोते हैं।

क्राई संस्था का भी कहना है कि भारत में बड़ी संख्या में बच्चे लापता हो जाते हैं। 2011 में पहले चार महीनों में ही बारह सौ साठ बच्चे लापता हो गए थे। इन खो जाने वाले सत्तर फीसदी बच्चों की उम्र बारह से अठारह साल के बीच होती है। इनमें से रिपोर्ट्स के अनुसार ही हजारों बच्चे अपने घर कभी लौट ही नहीं पाते। बच्चों के लिए काम करने वाले संगठनों को पुलिस के रवैये से भी नाराजगी है। उनका कहना है कि पुलिस अक्सर खोए हुए बच्चों की रिपोर्ट ही नहीं लिखती। हालांकि, यह भी सच है कि अनेक मामलों में पुलिस बच्चों को ढूंढ़ती भी है। दिल्ली में खोए

हुए बच्चों को उनके माता-पिता से मिलाने के लिए 'आपरेशन मिलाप' नामक कार्यक्रम भी चलाया जाता है। इस लेख की शुरुआत में पुलिस द्वारा खोए बच्चों का जिक्र है। यह भी कि उनमें से बहुत से बच्चों को अपने घर का पता या लैंडमार्क ही नहीं मालूम होता। इसके लिए पुलिस अभिभावकों के लिए जागरूकता अभियान भी चलाती है। पुलिस का कहना है कि अपने बच्चों को घर का पता ठीक से याद कराएं। हो सके तो फोन नम्बर भी उन्हें याद करा दें। जो बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते जब भी वे घर से बाहर जाएं, उनके कपड़ों पर घर का पता और फोन नम्बर लिख कर हमेशा रख दें।

वर्ष 2023 में मुम्बई पुलिस ने 'आपरेशन मुस्कान' के तहत आठ महीनों में पचास हजार खोए हुए बच्चों का पता लगाया था। पुलिस ने यह भी बताया था कि इन बच्चों के खोने के बड़े कारणों में पढ़ाई पर ध्यान न देना, मोबाइल का अधिक प्रयोग, गरीबी से बचने की चाहत, फिल्मों में काम करने की इच्छा, प्रेम-संबंध, माता-पिता से झगड़ा आदि शामिल हैं। साथ ही कई बार बच्चे उन लोगों से मिलने के लिए घर से भाग जाते हैं, जिनसे सोशल मीडिया पर चैट तो करते हैं मगर उनसे मिले भी नहीं होते। आजकल सोशल इनफ्लुएंसर बनने के चक्कर में भी बच्चे घर से भाग रहे हैं।

न जाने कितने माता-पिता ऐसे होते हैं, जो जीवन अपने खोए हुए बच्चों के इंतजार में गुजार देते हैं कि शायद एक दिन ऐसा हो कि बच्चा वापस आ जाए। कई बार बीस, बीस साल बाद बच्चे किसी सुखद संयोग के कारण माता-पिता के पास लौटते हैं। ऐसे में जिन माता-पिता के बच्चे पुलिस या अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं की तरफ से घर लौट आते हैं उनकी खुशी के कहने क्या।

मुम्बई में रेलवे पुलिस में कार्यरत हैं रेखा मिश्रा। वे अब तक सैकड़ों लापता बच्चों को उनके माता-पिता से मिलवा चुकी हैं। मुम्बई में देशभर से भागे हुए बच्चे आते हैं। इनकी भाषा समझना एक बड़ी चुनौती होती है। एक बार चेन्नई की तीन लड़कियों को अगवा करके मुम्बई लाया गया था। लेकिन वे केवल तमिल बोलती थीं। तब रेखा ने एक तमिल बोलने वाले की मदद से उन लड़कियों की बातों को समझा। चेन्नई से पता चला कि लड़कियों के माता-पिता ने उनके अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रेखा ने यह भी बताया कि कई बार माता-पिता ही इस बात पर ध्यान नहीं देते कि उनके बच्चे खो गए हैं। कई बार बहुत से बच्चे घर वापस नहीं जाना चाहते। यह बच्चे की इच्छा पर ही निर्भर करता है कि वह घर जाना चाहता है या पुनर्वास केंद्र। अगर वह घर नहीं जाना चाहता तो उसे पुनर्वास केंद्र भेजा जाता है और वहां उसके भरण-पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की व्यवस्था की जाती है।

क्षमा शर्मा

सीआरपीएफ भी आपरेशन 'नन्हे फरिश्ते' चलाती है। अभी तक इस योजना के तहत आठ सौ बाईस लड़के और चार सौ चौदह लड़कियों को बचाया जा चुका है। स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से इन्हें इनके माता-पिता से मिलवाया जाता है।

बेशक बहुत से बच्चे अपने माता-पिता से दोबारा मिल पाते हैं, इसमें अनेक संगठनों की भूमिका भी होती है। मगर ऐसे असंख्य बच्चे होते हैं जो एक बार घर से बिछुड़ने पर दोबारा कभी नहीं लौट पाते।

स्वयं सहायता समूहों को हटाने के फैसले से लाखों महिलाएं हो जाएंगी बेरोजगार

समूह एवं मजदूर संघ द्वारा झाबुआ कलेक्टर के नाम दिया गया ज्ञापन

माही की गूंज ,पेटलावद।

पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से ''सांझा चूल्हा योजना'' के अंतर्गत कार्यरत स्वयं सहायता समूहों को हटाकर मध्य प्रदेश सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नवाचार व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप प्रदेश में लाखों स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं बेरोजगार हो जाएंगी। स्वयं सहायता समूहों ने विपरीत परिस्थितियों में भी आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया है। इसके बावजूद भी, इन समूहों को हटाना एक ''हिटलरी आदेश'' के समान प्रतीत होता है जिसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए।

प्रशासन ने एक नया आदेश जारी किया है जिसके तहत अब समूहों से खाना न बनवाकर, आंगनवाड़ी केंद्र पर सहायिका के द्वारा ही खाना बनवाया जाएगा। इस आदेश के खिलाफ स्वयं सहायता समूह संघ पूरे प्रदेश में आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ''लखपति दीदी'' बनाने का सपना देख रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह फैसला महिलाओं को बेरोजगार करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। इस फैसले से नाराज समूहों ने आगामी दिनों में पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करने का मन बना लिया है। पेटलावद तहसील के स्वयं सहायता समूह के संघ पदाधिकारी एवं वनवासी कृषि एवं ग्रामीण मजदूर संघ ने संयुक्त रूप से झाबुआ कलेक्टर के नाम महिला एवं बाल विकास अधिकारी को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने समूह को हटाकर सहायिका से खाना बनाने के आदेश को निरस्त करने की मांग की है। यदि यह आदेश निरस्त नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। स्वयं सहायता समूह संघ ने स्पष्ट किया है कि वे इस अन्यायपूर्ण आदेश के खिलाफ अपने हक के लिए संघर्ष करते रहेंगे। इस आंदोलन में उनकी एकता और ताकत का प्रदर्शन होगा जो प्रशासन को अपना निर्णय वापस लेने के लिए मजबूर करेगा।

भरत भाई ने ग्रहण किया तिविहार संथारा

निखिशीलाजी मसा ने साधक सह संघ परिजन की सहमति से करवाये प्रत्याख्यान

माही की गूंज, थांदला।

जिन शासन में हर उपासक का अंतिम मनोरथ न जीवन से प्यार न मरने से भय रूप पंडित मरण का होता है। जिन आगम में अंतिम मनोरथ रूप पंडित मरण (संथारा) का परम सुख रूप फल बताया गया है जिसे पाने अनेक आत्म साधक पूरे जीवन भर अंतिम मनोरथ सिद्ध करने साधना आराधना व तपस्या करते रहते है। थांदला नगर का परम सौभाग्य है कि यहाँ जिन शासन गौरव जैनाचार्य पूज्य श्री उमेशमुनिजी मसा की कृपा पात्र एवं बुद्धपुत्र पूज्य श्री जिनेन्द्रमुनिजी मसा के आज्ञानुवर्ती महासती पूज्या श्री निखिलशिलाजी मसा दीर्घकाल से यहाँ माताजी मसा की सेवा में विराजित है जिसका लाभ सकल संघ को मिल रहा है। आज उन्ही के मुखारबिंद से संथारा साधक धर्मनिष्ठ सुश्रावक भरत भाई खिवेसरा (लिमड़ी वाले) को निरंतर छठे उपवास में तिविहार संथारे के प्रत्याख्यान करवा दिए गए। अब से वे केवल दिन में ही गर्म जल अथवा राख युक्त धोवन पानी का ही सेवन करेंगें।

भरत भाई लंबे समय से संत विहार सेवा में जाते रहे है। ऐसे में उनके मन में उमड़ते धर्म संस्कार व गुरु का आशीर्वाद का प्रतिफल ही कहा जा सकता है कि उनके अंतिम समय में पंच महाव्रतधारी चारित्र आत्मा के द्वारा संथारा ग्रहण करने को मिला। वही थांदला सकल जैन संघ उनके सरदार पटेल मार्ग पर व्यवसायी मणिलाल नागर के घर के सामने उनके बड़े भाई अभय खिवेसरा के यहां जाकर उनके दर्शन लाभ लेते हुए उन्हें नवकार महामंत्र, मांगलिक, स्तवन भजन आदि सुना कर आराधना में सहयोग कर रहे है। संघ अध्यक्ष भरत भंसाली ने भी उनके अंतिम मनोरथ सिद्ध होने की मंगल भावना के साथ सकल संघ से उन्हें धर्म सहयोग देने की अपील की है।

नौगांव आदिम जाति सहकारी संस्था का संचालक मंडल भंग

माही की गूंज, थांदला।

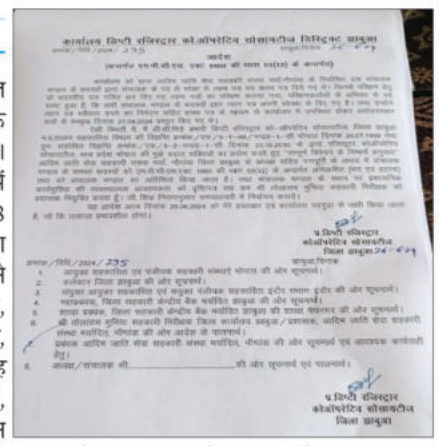

नौगांवा आदिम जाति सहकारी संस्था के संचालक मंडल को भंग कर दिया गया है। पिछले दिनों ग्राम नौगांवा में आदिम जाति सेवा संस्था के 8 सदस्यों ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। त्यागपत्र देने वालों में जवाहर बारिया, सम्बुड़ी मुकेश, गेमल सिंह, शंकरसिंह, रामसिंह, टीनूसिंह फतिया, सविता चिरंजीव, काना मिठिया आदि ने 22 जून को शपथ पत्र पर जिला मुख्यालय पर उच्च अधिकारियों को इस्तीफा सौंपा था। इन सदस्यों ने जिला अधिकारी से आदिम जाति सेवा संस्था को भंग कर नए अध्यक्ष का चुनाव कराने की मांग की थी। जिसके बाद 24 जून को दो और सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस स्थिति में संचालक मंडल के सभी सदस्यों के इस्तीफे के बाद महज अध्यक्ष ही बच गया था। झाबुआ सहकारी उपायुक्त डीसी भीड़े ने 10 संचालक सदस्यों के त्यागपत्र स्वीकार कर 26 जून को नौगांवा संचालक मंडल के निर्वाचित मंडल को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। सहकारिता उपायुक्त ने आगामी आदेश तक सहकारिता निरीक्षक तोलाराम मुनिया को उक्त संस्था में प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है।

थांदला नगर बनता जा रहा नकली बीज विक्रय का हब, खुदरा मुल्य से अधिक राशि वसूल रहे व्यापारी

किसानों को आ रही नकली बीज की समस्या को लेकर दिया ज्ञापन

माही की गूंज, थांदला।

मानसून समय पर आ चुका है, अंचल में वर्षा का दौर अब आगे भी चलता रहेगा। इन दिनों थांदला में खाद और बीज की दुकानों पर कृषकों की भीड़ देखी जा रही है। किसान वर्षभर अच्छी फसल की आस लिए खेत को तैयार करने में लग गया है। ऐसे में सबसे ज्यादा समस्या किसानों को बीज के लिए आ रही है। थांदला नगर जो कि नकली बीजों का हब बनता जा रहा है। पिछले वर्ष भी यहां पर नकली बीजों के प्रकरण दर्ज हुए थे। ऐसी किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर सोमवार को आदिवासी युवा क्रांति संघ ने एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी तरुण जैन को सौंपा है।

ज्ञापन देते हुए संघ के सदस्यों ने बताया कि थांदला बाजार में अमानक नकली बीच प्रचलित है। जिन्हें अप्रशिक्षित लोगों के द्वारा सिर्फ अधिक दाम कमाने के लिए विक्रय किया जा रहा है। साथ ही कपास, मक्का, सोयाबीन आदि बीजों की जो थैली पर अधिक खुदरा मूल्य (एमआरपी) लिखी रहती है, उससे तीन गुना ज्यादा पैसा किसानों से बीज व्यापारी ले रहे हैं।

वहीं फसल बोवनी के बाद किसानों को खाद और दवाई की भी जरूरत पड़ती है। वह खाद भी विक्रेताओं द्वारा एमआरपी से अधिक पैसे लेकर दी जाती है। ऐसे में आदिवासी हर प्रकार से ठगा जा रहा है। किसानों के साथ कालाबाजारी करते हुए व्यापारी धोखाधड़ी करते हैं।

थांदला में ऐसी दुकानें भी संचालित है जो लाइसेंसधारी नहीं है। संघ ने ज्ञापन देते हुए प्रशासन से मांग की है कि वह किसानों के हित में हस्तक्षेप करें। कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों को नियमानुसार कार्रवाई करें। अन्यथा संगठन द्वारा पूरे क्षेत्र में आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर आदिवासी युवा क्रांति संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे।

पल्स पोलियो अभियान के तहत घर-घर जाकर बच्चों को पिलाई दवा

माही की गूंज, सारंगी।

पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत जिला स्वास्थ्य अधिकारी के आदेश अनुसार बीएमओ डॉक्टर सुरेश कटारा के निर्देश अनुसार पल्स पोलियो अभियान 23 से 25 जून तक चलाया गया। अभियान के तीसरे दिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत सभी उप स्वास्थ्य केंद्र के गांव में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर जाकर 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई गई। बैंगनबड़ी उप स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत ग्राम छायन पाड़ा, हवारुंडा में भी बच्चों को दवाई पिलाई गई। बूथ सुपरवाइजर गुलाब सिंह द्वारा पूरे कार्यक्रम की विजिट की गई। इस अवसर पर बूथ सुपरवाइजर गुलाबसिंह, एएनएम निशा बंसल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता उपस्थित थी।

लायंस क्लब पेटलावद सेंट्रल की 2024-25 की नवीन कार्यकारिणी का गठन, अध्यक्ष बने निलेश भट्ट

माही की गूंज ,पेटलावद।

लायंस क्लब पेटलावद सेंट्रल की एक महत्वपूर्ण बैठक गत दिवस सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में सर्वसम्मति से लायन नीलेश भट्ट को 2024-25 हेतु लायन्स क्लब का अध्यक्ष बनाया गया। इस अवसर पर सचिव पद का दायित्व लायन गजेंद्र काग को दिया गया। कोषाध्यक्ष के रूप में अनुराग गौड़ तो प्रथम उपाध्यक्ष हेतु हरिओम पाटीदार को चुना गया। इस अवसर पर नवनियुक्त ला.अध्यक्ष निलेश भट्ट ने बताया कि पीड़ित मानवता में लगे क्लब को आज लगभग 28 वर्ष हो गए है। उक्त बैठक में क्लब के समस्त वरिष्ठ पदाधिकारी व सदस्यगण विशेष रूप से उपस्थित थे। उक्त बैठक में क्लब की आगामी सेवा गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा भी हुई व रूपरेखा बनाई गई। इस अवसर पर नवनियुक्त पदाधिकारियों को क्लब के समस्त सदस्यों ने बधाई दी व आगामी सफलतम कार्यकाल की शुभकामनाएं प्रेषित की तथा नवीन अध्यक्ष को विस्तार कार्यकारिणी गठित करने के लिए अधिकृत किया गया।

चंदनवाड़ी पहुंचा भोले भण्डारा सामग्री से भरा ट्रक, 27 जून से होगा भंडारा शुरू

लगातार 22 वर्षों से लगाया जा रहा है तीर्थ यात्रियों के लिए लंगर

माही की गूंज, थांदला।

विश्व प्रसिद्ध अमरनाथजी यात्रा के दौरान दाहोद, लिमखेड़ा, झाबुआ, कल्याणपुरा व थांदला के भोलें भण्डारा परिवार द्वारा कश्मीर के चंदनवाड़ी के प्लॉट नम्बर 3 पर एक माह तक विशाल लंगर लगाया जाता है। जिसमें यात्रियों को भोजन के साथ वहाँ रहने व अन्य आवश्यकता अनुसार सुविधाएं प्रदान की जाती है। इस हेतु सामग्री से भरा ट्रक चंदनवाड़ी के लिए रवाना किया गया जो वहाँ पहुँच गया। दाहोद में एक वृहद आयोजन करते हुए पीपलखुटा महंत 1008 दयारामदासजी महाराज एवं कबीर आश्रम सालिया गुजरात के महंत ऋषिकेशदासजी महाराज के पावन सानिध्य में दुर्गेश महाराज के द्वारा श्रीगणेशजी, भोलेनाथ भगवान, अन्नपूर्णा देवी सहित समस्त देवी देवताओं के लिए प्रारंभिक अनुष्ठान किया गया। उसके बाद भोलेनाथजी की महाआरती सम्पन्न करते हुए वहाँ प्रसादी वितरण की। इस अवसर पर आयोजन समिति द्वारा सभी अग्रज दानदाताओं का सम्मान किया गया। भण्डारें के लिए लिमखेड़ा, झाबुआ, कल्याणपुरा व थांदला भोलें भण्डारा परिवार ने भी अपने क्षेत्र से भोलें भक्तों द्वारा दी गई सहयोग राशि व रसद सामग्री दाहोद समिति को भेंट की।

इस अवसर पर भण्डारें की जानकारी देते हुए आयोजन समिति प्रमुख विक्की भाई ने बताया कि भोलें भण्डारा परिवार द्वारा लगातार 22 वर्षों से लंगर लगाया जा रहा है। जिसमें डूंगर मालवा से प्राप्त राशि, रसद व अन्य आवश्यक वस्तुओं को ट्रक द्वारा चंदनवाड़ी ले जाया जाता है। समिति द्वारा एक वहाँ भी एक जगह ली हुई है जहाँ भोजन बनाने का सामान, भण्डारें का शेड आदि अन्य सामग्री रहती है। जिसे भण्डारें की तय दिनांक से पूर्व ही तैयार कर लंगर सेवा शुरू कर दी जाती है। इस बार भी ट्रक 25 तारीख को चंदनवाड़ी पहुँच गया है व दो दिन में ही पूरा शेड वगैरह प्लॉट नम्बर 3 पर लगाकर 29 जून के पूर्व से ही लंगर शुरू कर दिया जाएगा। जो 29 जुलाई तक निरंतर चलेगा। आपको बता दे यात्रा 29 जुन से प्रारम्भ हो रही है जो 19 अगस्त तक चलेगी जिसमें देश और दुनिया से लाखों भोलें भक्त यात्रा में शामिल होते है। यात्रा में जहाँ शुरू में एक दिन में एक लाख से भी ज्यादा भक्त हिम शिवलिंग के दर्शन करते है व वहाँ के सुरक्षा में लगे जवानों का हौसला बढ़ाते है। वही प्रारंभिक एक माह के बाद के समय में प्रारंभिक दर्शनार्थियों की भीड़ से हिम शिवलिंग गल जाता है जिस से लोगों का आवागमन कम भी हो जाता है। पूरे हिंदुस्तान को एकता व अखंडता का पाठ पढ़ाते हुए देश की यह इक लौती धार्मिक यात्रा है जो लोगों को देश प्रेम से भी जोड़ती है। वहीं इस यात्रा में यात्रियों को केवल आवागमन में ही अर्थ लगता है उसके बाद भोजन से लेकर ठहरने तक की व्यवस्था निःशुल्क हो जाती है। जिसमें निःस्वार्थ से देश के दानदाताओं द्वारा सहयोग किया जाता रहा है।

यात्रा की दे रहे प्रेरणा तो थांदला के समर्थ महाराज वहाँ रह कर देंगें सेवा

इस धार्मिक आयोजन में व वहाँ की विषम परिस्थितियों में भी भोलें भण्डारा परिवार के सदस्यों का उत्साह कम नहीं हुआ है। दाहोद के विक्की भाई, राजा भाई, दुर्गेश महाराज, गुन्नु महाराज, केयूर मोठिया, राम भाई, बादल भाई, प्रकाश भाई, कृष्णकांत काका, रघु भाई, कमलेश भाई, झाबुआ के प्रकाश भाई, मनोज भाई, कुलदीप वर्मा, अमित पँवार, कनीराम, ईश्वर भाई कल्याणपुरा, थांदला से श्रीमंत अरोरा, पवन नाहर, मनोज उपाध्याय, प्रकाशचंद्र सोनी, मनोहरदास चौहान, सुधीर शर्मा, तुलसीराम मेहते, राजू धानक, आत्माराम शर्मा, मोहन चौहान, शैलेंद्र चौहान, राकेश जोझा, सोहनसिंह परमार, रूपसिंह सिंगाड़ आदि नगर में सभी धार्मिक आस्थावान लोगों को अमरनाथ जाने के लिए प्रेरित कर रहे है तो उनके पंजीयन में सहायक भी बन रहे है। भोलें भण्डारा परिवार के समर्थ महाराज लगातार दूसरी बार चंदनवाड़ी में रहकर सभी भोलें भक्तों की सेवा में सहयोग देंगें। इस अनुष्ठान व अर्थ सहयोग के लिए पवन नाहर श्रीमंत अरोरा ने सभी दानदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया है।

संपादकीय

लोकतंत्र की दरकार

देश में लंबे चले चुनाव अभियान और चुनाव परिणाम के बाद अस्तित्व में आयी 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राजग की लगातार तीसरी पारी गठबंधन सरकार के रूप में सामने आई है। निश्चित रूप से इस बार विपक्षी गठबंधन पिछले दशक के मुकाबले ज्यादा मजबूत बनकर उभरा है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी का विपक्ष का नेता चुना जाना साफ बताता है कि आने वाले दिनों में राजग सरकार की राह आसान नहीं रहने वाली। इस संक्षिप्त सत्र के दूसरे दिन लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सत्ता-पक्ष व विपक्ष के बीच जो तनातनी सामने आई, वह पिछले सात दशकों के मुकाबले अभूतपूर्व है। विपक्ष एक ओर लोकसभा उपाध्यक्ष पद देने की मांग कर रहा था, तो सत्ता पक्ष ऐसा करने को तैयार नहीं था। जाहिर इस टकराव के बीच लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराने की स्थितियां बनी हैं। हालांकि, राजग सरकार के पास चुनाव पूर्व गठबंधन के चलते पूर्ण बहुमत है, लेकिन विपक्ष इस चुनाव को अपनी एकजुटता के रूप में एक प्रतीकात्मक दबाव के रूप में दिखाना चाहेगा। बहरहाल, बेहतर होता कि लोकसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदों पर चयन सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच सहमति से होता। इसी तरह नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाने के लिये नियुक्त प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर भी सत्ता पक्ष व विपक्ष में तनातनी देखी गई। वरिष्ठता के क्रम में इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस की दावेदारी की गई थी। बहरहाल, 18वीं लोकसभा की शुरुआत में ही पक्ष-विपक्ष के बीच तनातनी की शुरुआत स्वस्थ लोकतंत्र के लिये अच्छा संकेत तो कदापि नहीं है। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि 17वीं लोकसभा के दौरान टकराव के चलते तमाम सत्रों में कामकाज बुरी तरह प्रभावित रहा। उल्लेखनीय है कि दिसंबर, 2023 में शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में घुसपैठ के मामले में बहस की मांग पर कथित दुर्व्यवहार हेतु 141 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया था। जिसमें 95 लोकसभा सदस्य थे।

उम्मीद की जानी चाहिए 18वीं लोकसभा में वैसे दृश्य फिर न देखने को मिलें। जनता अपने प्रतिनिधियों को इस लिये चुनकर संसद में भेजती है ताकि वे उनके इलाके के विकास को नई दिशा दे सकें। लेकिन पहले दिन विपक्षी नेताओं द्वारा संसद में संविधान की प्रतियों के साथ एकजुटता दर्शाना और कतिपय सत्तारूढ़ दल के सांसदों के शपथ ग्रहण के दौरान नारेबाजी को देखकर लगता है कि विपक्ष ज्यादा मुखर होकर सरकार के लिये चुनौती पेश करता रहेगा। बहरहाल, किसी भी लोकतंत्र की खूबसूरती इस बात में है कि सरकार सहमति से चले। साथ ही विपक्ष भी जिम्मेदार भूमिका में नजर आए। कुल मिलाकर हंगामे, बहिष्कार व नारेबाजी के बजाय रचनात्मक व गरिमामय भूमिका की दरकार है। स्वस्थ लोकतंत्र की दरकार है सरकार के निर्णयों में हर छोटे-बड़े राजनीतिक दल की भागीदारी हो। सत्तारूढ़ दल को भी इस बात का बखूबी अहसास होना चाहिए कि इस बार विपक्ष मजूबती के साथ लोकसभा में उपस्थित हुआ है। उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता है जैसा कि राजग सरकार के पिछले दो कार्यकालों में नजर आया था। ऐसे में राजग सरकार को विपक्षी सहयोग से सदन को चलाना होगा। विपक्षी नेताओं के साथ मित्रवत व्यवहार ही सरकार की कार्यशैली को रवानगी देगा। अन्यथा लगातार टकराव की स्थिति बनी ही रहेगी। जिससे सत्तापक्ष व विपक्ष को लगातार बचने का प्रयास करना होगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है। जिसे सार्थक बनाने का दायित्व सत्तारूढ़ व विपक्षी सांसदों के पास है। लगातार टकराव व हंगामे का दुनिया में कोई अच्छा संदेश नहीं जाएगा। किसी भी कलह से घिरी सरकार पर कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जिससे देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि भी प्रभावित होती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि 18वीं लोकसभा में पक्ष-विपक्ष मनभेद-मतभेद भुलाकर नये भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। देश के सामने बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, महंगाई और विकास से जुड़ी तमाम चुनौतियां खड़ी हैं, सरकार और विपक्ष को इसका एकजुट होकर मुकाबला करना चाहिए।

पंजाब को चाहिए सर्वांगीण विकास का दृष्टिकोण

कुछ दिन पहले मैं किताबों की दुकान पर यह देखने गया कि नया क्या आया है। मैंने कुछ किताबें चुनीं और बाहर निकलने ही वाला था कि एक युवा महिला कहने लगी कि वह मुझ से कुछ बात करना चाहती है। मैं उसे और दिल्ली में उसके परिवार को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। वह काफी उद्वेलित लग रही थी और उसने सीधे मुझसे सवाल दागा कि लोकसभा चुनाव में अमृतपाल सिंह और सरबजीत सिंह खालसा की जीत के पंजाब के भविष्य को लेकर क्या मायने हैं। मैंने उसका डर दूर करने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया। किताबों की दुकान जैसे सौम्य माहौल में हुई इस दोस्ताना बहस ने मुझे हिला दिया और अचानक शुरू हुए इस संवाद से पैदा हुई विचार प्रक्रिया को मैंने झटकने का प्रयास किया। मैं घर पहुंचा, तभी रिश्ते में अग्रज लगते भाई का फोन आया, जो सेना में ऊंचे ओहदे से एक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और इन दिनों पंजाब में बसे हुए हैं। उन्होंने भी पूछा कि पंजाब में क्या चल रहा है। मैंने उन्हें भी नरमी भरी बातों से इस चिंता से निकालने की कोशिश की और सुझाव दिया कि वे और उनकी पत्नी कुछ दिनों के लिए कहीं घूम आएं। अगले कुछ दिनों तक मुझे पंजाब से रिश्तेदारों, मित्रों और परिचितों की अनेक फोन कॉल्स आईं, सब एक जैसे सवाल पूछ रहे थे, आधी गंभीरता, आधे उत्साह युक्त। पंजाब में एक दशक तक चली हिंसा की सुनामी के वक्त भी, सतह के नीचे, चिंता की तरंगें थीं। तो क्या गुजरा अतीत, वर्तमान और भविष्य बनने जा रहा है?

हिंसा की उस कहानी को पकने में कई साल लगे थे और मैं उनमें एक हूं जिन्होंने अपनी आंखों से इसे आगाज़ से अंत तक घटित होते देखा। आम धारणा के विपरीत, अंतिम काली छाया तक पहुंचने से पहले, इसने विकसित होने में कई साल लिए थे और इस बुरी कहानी के नाटकीय पात्र सर्वविदित हैं। शतरंज की बिसात पर मोहरे चलाने वाली राजनीतिक और सामाजिक शक्तियों के बारे में भी सबको पता है, लेकिन ग्रीक कहानियों में त्रासदी की नियति की भांति हम भविष्य के वक्त की चाल को देख तो सकते हैं लेकिन दखल देकर उसकी धारा को मोड़ नहीं दे सकते और त्रासदी है कि वह अपनी राह पर चलते हुए, रक्तरंजित अंजाम को पा जाती है। यह सब बहुत पहले की बात नहीं है और जनता की याद?दाश्त वैसे भी कमज़ोर होती है... तो क्या हम फिर पुनरावृत्ति की राह पर हैं? मैं यह तो नहीं कहना चाहूंगा लेकिन फिर सरकार चुप क्यों हैं? राजनीतिक दल क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? मीडिया किसलिए मूक है और सिविल सोसायटी भी चुप क्यों हैं? कहां से आये हैं ये दो लोग और किस प्रकार संसद के सदस्य तक चुन लिए गये हैं? यही वक्त है ऐसे सवाल पूछने का और यही समय है जब सरकार और राजनीतिक दल इनके जवाब दें। आज की तारीख में लगता है राजनीतिक दलों का एक ही ध्येय है दृ संसद, विधानसभा, नगर निकाय और पंचायत के चुनाव लड़ना और जीत पाना। उनकी एकमात्र इच्छा सभी स्तरों पर ताकत हासिल करना है, बगैर किसी जवाबदेही के। सरकार को अब तक पता होना चाहिए था कि लोग चिंतित हैं, पंजाब में क्या हुआ, इन चुनावी नतीज़ों की व्याख्या करने को उसे मूल कारण तक गहरे उतरना चाहिए, यहां तक कि कंगना रनौत थप्पड़ कांड में भी।

पिछले दो दशकों में सरकारें बनीं और गईं, लेकिन उनमें किसी एक ने भी 1980 और 1990 के दशक में जो कुछ हुआ, उसकी वजहें जानने की कोशिश नहीं की, और न ही कोई सबक लिया। किसी सरकार ने युवाओं की शिक्षा, रोजगार, बुनियादी ढांचा विकास और उद्योग स्थापना के लिए बृहद योजना नहीं बनाई। कहने का अर्थ यह नहीं कि पंजाब में कोई विकास नहीं हुआ। हरित क्रांति और इसके बाद के सालों ने पंजाब को सुनहरे दिन दिए और भारत को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। एक आईआईटी, एक आईएमएम, एक उच्चकोटि का मेडिकल शिक्षा संस्थान और सड़क तंत्र जरूर बना है लेकिन यह बहुत कम और बहुत देर से हुआ और अधिकांश अंदरूनी ग्रामीण इलाका आज भी पुरानी पड़ चुकी कृषि अर्थव्यवस्था और बंटवारे के बाद छोटे होते खेतों से घटती कमाई के चक्र में फंसा हुआ है, जिससे किसान के सिर पर भारी कर्ज चढ़ जाता है और वे आत्महत्या तक कर लेते हैं। रोजगार के स्रोत जैसे कि सशस्त्र सेना में भर्ती भी सिकुड़ी है, लिहाजा विदेशी मुल्कों की ओर बड़े पैमाने पर युवाओं का पलायन हो रहा है। इसके चलते नौजवान और बड़ों में रोष सुलग रहा है

जिसका दोहन अतिवादी तत्व कर सकते हैं। राजनेताओं की प्रवृत्ति झूठे वादे, मुफ्त की रेवड़ियां बांटने और मिथ्या आंकड़ों से बहलाने की होती है, इससे स्थिति और बिगड़ती हैदृ वे किसे बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं? नशे का सेवन पूरे देश में आम हो चला है और देशभर में इसकी रोकथाम के रूप में महज यहां-वहां की जा रही छापेमारी है या छोटी मछलियां पकड़ी जाती हैं। नशा माफिया का एक भी बड़ा व्यापारी या इसमें पूंजी लगाने वाला गिरफ्तार नहीं हुआ है।

मुख्यधारा के राजनीतिक दल निरंतर धुर-दक्षिणपंथियों के लिए मैदान खाली छोड़ रहे हैं। हालिया लोकसभा चुनाव में, शिरोमणि अकाली दल का वोट शेयर घटकर 13.4 फीसदी रह गया। हालांकि 18.5 प्रतिशत वोटों के साथ भाजपा की कारगुजारी भी कोई बढ़िया नहीं रही। अकाली दल का प्रदर्शन 2022 के विधानसभा चुनाव में पाए 18.3 फीसदी वोटों से नीचे गिरा है। मैंने अकाली दल का नाम इसलिए लिया क्योंकि यह वह दल है जिसने कभी पंजाबी सूबा मोर्चा जैसे आंदोलन चलाए और कांग्रेस के बाद देश की दूसरी सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। दिवंगत प्रकाश सिंह बादल पांच बार मुख्यमंत्री बने और कद्दावर शख्सियत थे जिन्होंने राजनीतिक मुद्दों पर अपना अडिग रुख कायम रखते हुए अनेक बार जेलें काटी, इनमें इमरजेंसी से लेकर सतलुज-यमुना लिंक नहर को लेकर चलाए आंदोलन भी शामिल हैं। हालांकि अतिवादियों के दबदबे वाले 1980 और 90 के कालखंड में उनकी पार्टी ने भी अन्य मुख्यधारा दलों की भांति मूक-दर्शक बने रहना चुना था, जिससे कि सारा मैदान अतिवादियों के लिए खुला छूट गया। इससे आगे, आतंकवादियों के निर्देशों का पालन करते हुए उनकी पार्टी ने 1992 में हुए विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया था।

इसी प्रकार, हालिया इतिहास के सबसे बड़े किसान आंदोलन के वक्त कांग्रेस और उसका नेतृत्व नदारद रहा, जब दिल्ली में बनाई गई कृषि नीतियों के विरोध में पंजाबी किसानों ने मोर्चा लगाया। पंजाब जैसे कृषि प्रधान सूबे में इस किस्म की अनुपस्थिति दर्ज करवाकर कांग्रेस ने एक प्रकार से राजनीतिक आत्महत्या की है। बाद में, इसका सत्यापन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के रूप में हुआ (आगे चलकर राज्यस्तरीय नेता भाजपा में चले गए)। उस समय पंजाबियों ने स्थापित राजनीतिक दलों और परिवारों को नकार दिया और आम आदमी पार्टी को मौका दिया। 'आप' हालांकि कोई विशेष प्रभाव नहीं बना पाई और इसका पता लोकसभा की 13 सीटों में केवल 3 पर मिली जीत से चलता है। इसका वोट शेयर 2022 के विधानसभा चुनाव में मिले 45 फीसदी मतों से घटकर लोकसभा चुनाव में 26 फीसदी रह गया। कहने का भाव यह कि मुख्यधारा के दल अपना जनाधार अमृतपाल जैसों के मुकाबले खोते जा रहे हैं, जिससे राजनीतिक बहसें तीखी और अतिशयी बन रही हैं। यह लगभग वैसा है जब अतिवादियों के फरमान का पालन करते हुए मुख्यधारा दलों को चुनाव का बहिष्कार करना पड़ा था। यह स्थिति सूबे और इसके लोगों के हित में नहीं है।

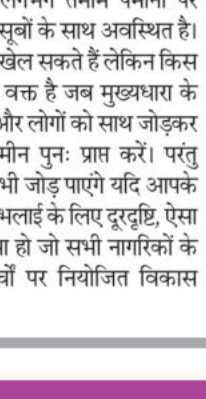

गुरबचन जगत

अब जबकि धुर दक्षिणपंथी अपने पुराने शबाब में लौटते दिखाई दे रहे हैं, पंजाब और भारत में सुरक्षा और शांति को खतरा बनेगा, नाना प्रकार की साजिश कथाएं फैलेंगी और अगर वक्त रहते सड़न को नहीं रोका तो जिस शांति को स्थापित करने में दशक लगे वह जाती रहेगी। इस सड़न के कारक हालांकि हकीकत से जुड़े हैं क्योंकि बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा के मुद्दों पर ध्यान देने से बचा जा रहा है। विकास सूचकांक में पंजाब काफी वर्ष पहले अपना अगुआई वाला स्थान गंवा चुका है और अब विकास एवं संवृद्धि के लगभग तमाम पैमानों पर निचली श्रेणी के सूबों के साथ अवस्थित है। राजनेता आग से खेल सकते हैं लेकिन किस कीमत पर? यही वक्त है जब मुख्यधारा के दल जोर लगाएं और लोगों को साथ जोड़कर अपनी गंवाई जमीन पुनः प्राप्त करें। परंतु आप लोगों को तभी जोड़ पाएंगे यदि आपके पास पूरे सूबे की भलाई के लिए दूरदृष्टि, ऐसा समावेशी नजरिया हो जो सभी नागरिकों के लिए तमाम मोर्चों पर नियोजित विकास करने वाला हो।

संसद में मोदी सरकार की अग्नि परीक्षा

सनत कुमार जैन

तीसरी बार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर पर कांटों का ताज है। नरेंद्र मोदी 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहे। 10 साल केंद्र में प्रधानमंत्री रहे। नरेंद्र मोदी की सत्ता का यह 24वां साल है। 23 साल तक मोदी का सत्ता में एकछत्र राज रहा है। 23 साल तक सदन में उनके पास पूर्ण बहुमत था। पहली बार वह अल्पमत की सरकार के प्रधानमंत्री बने हैं। विपक्ष इस समय जोश से भरा हुआ है। भले उसके पास स्पष्ट बहुमत ना हो। लेकिन उसमें इतनी ताकत है, कि वह सरकार से पूरी ताकत से मुकाबला कर सके। सदन के अंदर अब सत्ता पक्ष मनमानी नहीं कर सकेगा। बहुमत के आधार पर कानूनो को हो-हल्ले के बीच पास नहीं करा पाएंगे। कानून पास कराने के पहले सदन के अंदर चर्चा भी करानी होगी। लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर भी दबाव होगा, सरकार द्वारा जो भी बिल सदन में पेश किए जा रहे हैं, वह नियम और कानून के तहत पेश हों। उन पर विधिवत चर्चा हो। चर्चा होने के बाद मतदान हो। उसी के बाद बिलों की स्वीकृति प्रदान की जाए। पिछले 10 वर्षों में कई कानून नियम विरुद्ध सदन में पेश किए गए। सदन से उन्हें अध्यक्ष ने पास भी करा दिया। मनी बिल के रूप में ऐसे बहुत सारे नियम और कानून बनाए गए। जो मनी बिल के रूप में सदन के अंदर स्वीकृत ही नहीं हो सकते थे। पिछले 10 साल में संसद सदस्यों के अधिकार भी सदन के अंदर कम हुए हैं। सरकार के मुकाबले सदन के अधिकार सरकार के पास चले गए। बहुत सारे कानून बिना किसी चर्चा के ध्वनि मत से पारित करा दिए गए। तीन अपराध कानून भी उसी श्रेणी में आते हैं। विपक्षी सांसदों को निष्कासित कर सदन में कुछ मिनटों के अंदर ध्वनि मत से कानूनों को पास करा दिया गया। इससे अध्यक्ष पद की साख भी पहले की तुलना में काफी कमजोर हुई है। अब विपक्ष के पास सदन के अंदर ताकत है। अध्यक्ष भी सदन के अंदर विपक्ष की ताकत को अनदेखा नहीं कर सकता है। सदन के अंदर जो भी बिल पेश किए जाएंगे, वह नियम के अंतर्गत सरकार को अध्यक्ष की अनुमति से पेश करने होंगे। ऐसे बिलों पर संसद के अंदर बहस भी होगी। सभी सांसदों को बोलने का मौका मिलेगा। मोदी सरकार ने 10 साल में जो

कानून पारित कराए हैं। उनको लेकर विपक्ष समय-समय पर अपनी नाराजी जताता रहा है। संसदीय परंपराओं का पालन नहीं किया गया। मजदूरों से संबंधित श्रम कानून, न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून, 3 अपराध कानून, दिल्ली सरकार के अधिकारों पर कटौती, चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून और मनी बिल के तहत जो कानून पास कराए जा रहे थे। संसद में विपक्ष की जो अनदेखी सरकार द्वारा की जा रही थी। अब उन सारे मामले में टकराव बनना तय है। संशोधन या अन्य माध्यमों से विपक्ष चर्चा करने की हर संभव कोशिश करेगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में टकराव बढ़ेगा। 18वीं लोकसभा के प्रथम सत्र में विपक्ष पेपर लीक, अग्नि वीर, मणिपुर, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार को तगड़ी चुनौती देता हुआ दिख रहा है। सरकार ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को लेकर भी विपक्ष के साथ सहमति बनाने का कोई प्रयास सरकार द्वारा नहीं किया गया। जिसके कारण स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार अध्यक्ष पद के लिए लोकसभा में चुनाव होगा। जिस तरह की स्थितियां लोकसभा में बनती दिख रही हैं, उसमें एक ज्योतिषी जो इन दिनों देश एवं दुनिया में बड़े चर्चित हैं, उनका नाम है- राजीव नारायण, जिन्होंने भविष्यवाणी की है। भाजपा के खिलाफ जन असंतोष बढ़ेगा। विपक्षी दलों का विरोध भी बढ़ेगा। भाजपा के अंदर ही बगावत होगी। भाजपा के लिए अपनी सत्ता बनाए रखना बड़ा मुश्किल होगा। उसी तरह की स्थिति सदन के अंदर बनती हुई दिख रही है। तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सहयोगी दलों और भाजपा के ही वरिष्ठ नेताओं से जिस तरह की चुनौती मिल रही है, उससे मोदी के लिए सत्ता में बने रहना, दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीन पटनायक के साथ जो विश्वासघात का खेला किया है, उसके कारण नवीन पटनायक भी अब उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। उड़ीसा का असर अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर भी पड़ रहा है। रही सही कसर अयोध्या और राम मंदिर पूरी कर रहे हैं। मुख्य सहयोगी दलों को सरकार में महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिए गए। अध्यक्ष पद भी उन्हें नहीं दिया गया। जिसके कारण सहयोगी दलों से भी सरकार को चुनौती मिल रही है। अयोध्या के रेलवे स्टेशन की एक दीवार टूट गई। अयोध्या का मुख्य मार्ग अटल पथ ढह गया। राम मंदिर की छत से पानी रिसने लगा। गर्भ ग्रह में पानी भर गया। तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहीं से भी अच्छे समाचार नहीं आ रहे हैं। तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने अस्तित्व को बचाए रखने की लड़ाई लड़ना पड़ रही है। देखना यह है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे अपनी सत्ता को बचाए रखते हैं।

बाजार पर मेहरबान सरकार 3

चैतन्य भट्ट

बिना जमीनी जांच-पड़ताल के निर्णय लेने की पहचान बनती जा रही प्रदेश सरकार ने एक और तुगलकी निर्णय लिया है कि प्रदेश के16 प्रमुख शहरों के बाजार 24 घंटे खुले रहेंगे। बकौल मुख्यमंत्री इसका लाभ कारोबार और रोजगार वृद्धि और सरकारी राजस्व बढ़ाने में मिलेगा जिससे अर्थव्यवस्था को पंख लगेंगे। रेस्टोरेंट, मॉल, होटल, बिजनेस सेंटर और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े कार्यालय दिन-रात चलेंगे। कहने को बार और शराब दूकानों को इससे पृथक रखा गया है मगर कौन नहीं जानता कि ये व्यवसाय अंदर वाली खिड़की से दूकानदारी चलाने के हुनर के उस्ताद हैं। कहा जाता है कि श्रम विभाग ने भोपाल और इंदौर में यह व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लाने की योजना बनाई थी मगर मुख्यमंत्री ने सभी नगर निगम क्षेत्रों में लागू करने के लिए कह दिया।

यह छुपा हुआ सत्य नहीं है कि व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और दुकानदारों द्वारा किस बेशर्मी से श्रम कानूनों का उल्लंघन किया जाता है। श्रमिकों के लिए दिन में आठ घंटे कार्य का प्रावधान है मगर 12- 12 घंटे काम लिया जाता है और निर्धारित अवकाश के दिन भी दुकानें खोली जाती हैं। श्रम कानूनों में 8 घंटे से अधिक कार्य करने और अवकाश दिवस के लिए अतिरिक्त मजदूरी का प्रावधान है मगर सामान्य कार्य दिवस पर भी शासकीय दर से मजदूरी नहीं मिलती। अतिरिक्त अवधि तक कार्यरत रहने से श्रमिकों को शरीरिक और मानसिक रुप से परेशानी तो आती ही है, वे अपने व परिवार के लिए समय भी नहीं निकाल पाते जिसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। विशेषतः रेस्टोरेंट और खाने पीने के सामान की दूकानों के श्रमिकों में बहुतायत संख्या बाल मजदूरों की होती है जो कानूनन अपराध है। यह असंगठित श्रमिक इस अन्याय को चुपचाप सहने पर मजबूर हैं। संबंधित विभागीय अफसर सब कुछ जानकर भी लापरवाह बने रहते हैं। अच्छा होता अगर 24 घंटे बाज़ार गुलजार रखने के निर्णय के साथ साथ शासन इन विसंगतियों पर भी ध्यान देता। मगर व्यवसायिक हितों के सामने श्रमिक हित बौने साबित हो रहे हैं।

कानून व्यवस्था एक अन्य पहलू है जिस पर यह निर्णय भारी पड़ने वाला है। राज्य पुलिस मानव संसाधनों की गंभीर कमी से जूझ रही है जिसके चलते इस अतिरिक्त कार्य के लिए उसके पास उपलब्ध संसाधन नाकाफ़ी होंगे। मध्य प्रदेश पुलिस की अपनी डाटा रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 480, उत्तर प्रदेश में 123, पंजाब में 236, महाराष्ट्र में 165, हरियाणा में 209 की तुलना में मध्य प्रदेश में प्रति लाख आबादी पर 117 पुलिसकर्मी हैं। पूरे देश के औसत की बात करें तो यह आंकड़ा 124 है। विभिन्न पुलिसीय विभागों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष 25 से लेकर 40 प्रतिशत तक कम पुलिस बल है जिसके

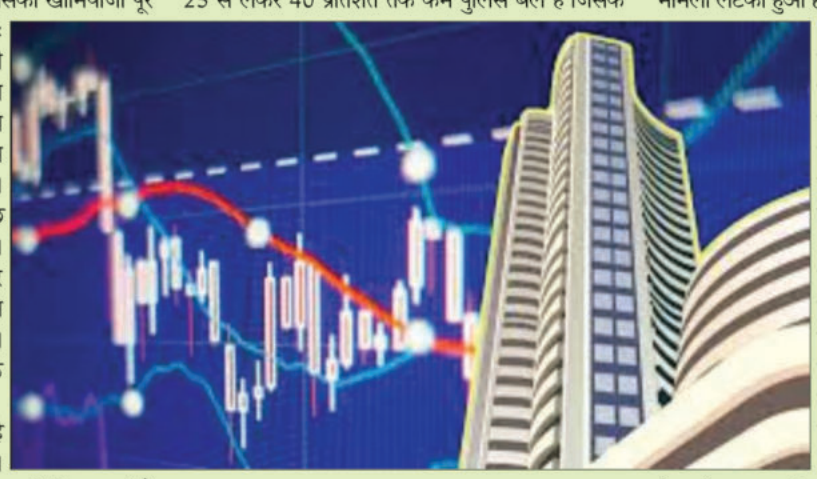

कारण अपराध बढ़ रहे हैं। मगर आउटसोर्सिंग नामी व्यवस्था से चहेतों को फायदा पहुंचाने की शौकीन सरकार इस कमी पर ध्यान देने को तैयार नहीं दिखती। भर्तियों की प्रक्रिया प्रारंभ होती भी है तो इतना समय ले लेती है कि आदमी भूल ही जाए कि कब आवेदन दिया था ? पदोन्नतियां अटकी हुई हैं और महत्वपूर्ण पद खाली हैं। जबलपुर और ग्वालियर जैसे महानगरों में पुलिस कमिश्नर की पदस्थापना का महत्वपूर्ण मामला लटका हुआ है।

24 घंटे बाज़ार खोले रखने के निर्णय से व्यापार और राजस्व वृद्धि का राग अलापने वाली सरकार संभवतः यह भूल गई है कि इसके लिए उपभोक्ता की जेब में पैसा होना भी जरूरी है। रिकार्ड तोड़ महंगाई और बेरोज़गारी ने नागरिकों की कमर तोड़ कर रख दी है। आम आदमी अपनी रोजमर्रा की निहायत जरूरी आवश्यकताएं भी कर्ज लेकर पूरी करने पर मजबूर है। बड़ी बड़ी कंपनियां परेशान हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद बाजार में उनके उत्पादों की मांग नहीं बढ़ रही है। ऐसे में यह सरकारी निर्णय न सिर्फ अव्यावहारिक है बल्कि आम नागरिक के जले पर नमक छिड़कने जैसा है।

आम नागरिक के नजरिए से देखा जाए तो ऐसी व्यवस्था की जरूरत सरकारी कार्यालयों में ज्यादा है जिनमें सामान्य कार्य दिवसों में भी कोई काम करवाना टेढ़ी खीर है। मगर वहां पर सरकार का रुख बजाय कार्य दिवस और घंटे बढ़ाने के राजनैतिक कारणों से अवकाश दिवस बढ़ाने पर रहता है। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अधिकारी कर्मचारी आम नागरिक से ठीक से बात करना भी अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। भृष्टाचार के स्तर की बात करना ही बेमानी है। नागरिक सेवाओं के समयबद्ध निराकरण के लोक सेवा गारंटी अधिनियम जैसे कानून लाए तो जाते हैं मगर इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई जाती कि वास्तविक धरातल पर वे कानून कितने कारगर सिद्ध हो रहे हैं। राजनीतिक तुष्टिकरण के लिए ब्लाक को तहसील और तहसील को जिला बनाने जैसी उछल कूद मचती रहती है मगर संसाधनों की कमी से न सिर्फ वास्तविक स्थिति जहां की तहां बरकरार रहती है बल्कि अधिकार क्षेत्र के रटे रटाए बहानों से नागरिक सेवाओं के निराकरण में और भी अधिक विलंब होने लगता है।

जब प्रदेश के मुखिया निर्णय ले ही चुके हैं कि बाजारों को सातों दिन चौबीसों घंटे गुलज़ार रहना है तो वह तो होकर रहेगा। मगर क्या सरकार ने इस तथ्य को परखने का कोई मापदंड निर्धारित किया है कि इस परिवर्तन से व्यवसाय और रोजगार के साथ साथ सरकारी राजस्व वृद्धि के उद्देश्य कहां तक सफल रहे हैं ? और इस परिवर्तन से संभावित कानून व्यवस्था और श्रम कानूनों के उल्लंघन को रोकने और बाजार श्रमिकों को शोषण से बचाने की ठोस व्यवस्था सुनिश्चित की गई है या नहीं ? प्रश्न तो सामयिक हैं मगर उस व्यवस्था में, जहां सरकारी निर्णयों पर प्रश्न उठाया जाना विद्रोह माना जाता हो, उत्तरों की अपेक्षा करना मृगतृष्णा ही है।

कृषि उपनिदेशक ने भाजपा विधायक के देवर पर दर्ज करवाई एफआईआर

गुना।

मध्य प्रदेश में गुना जिले के चंचौरा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की विधायक प्रियंका मीणा के देवर अनिरुद्ध मीणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एग्रीकल्चर डिप्टी डायरेक्टर उपनिदेशक को बंधक बनाने, धमकाने और 50 लाख रुपये की मांग करने के आरोप में अनिरुद्ध के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। डिप्टी डायरेक्टर अशोक कुमार उपाध्याय ने गुना के पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा को इस संबंध में एक पत्र लिखा है।

पत्र में सिन्हा ने लिखा, 'चंचौरा भाजपा विधायक प्रियंका मीणा के देवर और विधायक प्रतिनिधि अनिरुद्ध मीणा ने मुझे एक घंटे तक बंधक बनाए रखा और 50 लाख रुपए की मांग की। उसने मेरे साथ गाली-गलौज की।' चंचौरी की सबडिविजनल पुलिस अधिकारी दिव्या राजावत ने बताया, 'अनिरुद्ध मीणा और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294 (अश्लील कृत्य), 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना), 353 (सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए हमला अैर आपराधिक बल का प्रयोग) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच चल रही है।'

अपनी शिकायत में उपाध्याय ने कहा, 'अनिरुद्ध मीणा ने 20 जून को मुझे फोन किया और कहा कि विधायक महोदया ने मुझे पेंची ऑफिस बुलाया है। चूंकि मैं स्कूल चलो अभियान के लिए ड्यूटी पर था, इसलिए मैं नहीं गया। इसके बाद मुझे 21 जून को आने के लिए कहा गया। मैं विभाग के अधिकारी तुलसीराम सोलंकी और एक ड्राइवर के साथ उनके कार्यालय पहुंचा। वहां मेरी मुलाकात अनिरुद्ध मीणा से हुई। उन्होंने खाद की उपलब्धता के बारे में पूछा। मैंने उन्हें व्हाट्सएप पर जानकारी भेजी।'

डिप्टी डायरेक्टर ने आगे लिखा, 'बाद में मैंने उनसे कहा कि मुझे दोपहर 12 बजे से खाद को लेकर कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग के लिए जाना है। उन्होंने मुझे अपने बगल वाले दूसरे कमरे में बैठा दिया। फिर मीणा और एक अन्य व्यक्ति आया और दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया और अपने पास रख लिया। उन्होंने कहा कि जब बुलाया जाए तो एक घंटे के अंदर उपस्थित हो जाना। दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं, इसलिए मैं विरोध नहीं कर सका। कमरे में लाठी आदि भी रखी हुई थी।'

शिकायत में उन्होंने कहा, 'उन्होंने कहा कि तुम पिछले छह सालों से यहां काम कर रहे हो। तुम बहुत पैसा कमा रहे हो। 50 लाख रुपए दो, क्योंकि चुनाव में करोड़ों खर्च हो चुके हैं। अगर तुम नहीं दोगे तो विधानसभा में तुम्हारे खिलाफ सवाल उठाए जाएंगे। अगर मैंने यह बात किसी को बताई तो उन्होंने मुझे झूठे मामले में फंसाने या जान से मारने की धमकी भी दी।'

घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को कहा कि किसी भी गलत काम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, 'मैंने आज अखबार में पढ़ा। मैंने साफ कहा है कि गुना, शिवपुरी और अशोकनगर में चाहे चेयरमैन हो, विधायक हो, मेरा रिश्तेदार हो, सहकर्मी हो, पार्टनर हो, कोई भी हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है।' वहीं अनिरुद्ध मीणा ने आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा, 'हमें खाद से जुड़ी शिकायतें मिल रही थीं, इसलिए हमने डिप्टी डायरेक्टर उपाध्याय से इस बारे में चर्चा की। वे झूठे आरोप लगा रहे हैं।'

चलती ट्रेन में अवैध वेंडरों के बीच हुई चाकूबाजी

माही की गूंज, रतलाम।

मध्यप्रदेश में गुंडागर्दी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला रतलाम रेलवे स्टेशन का है। जम्मूतवी ट्रेन में अवैध वेंडरों के बीच मंगलवार रात मारपीट हो गई। चलती ट्रेन में एक वेंडर ने तीन वेंडरों को चाकू मारकर घायल कर दिया। ट्रेन के डिब्बे में भगदड़ की स्थिति बन गई। रतलाम रेलवे स्टेशन से तीनों को जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चाकू मारने वाले को पीट दिया। हंगामा होने लगा तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया।

रतलाम के राम मंदिर इलाके में रहने वाला उमेश (20) और उसका भाई गोलू उर्फ नरेंद्र (28) निवासी मोतीनगर और बहन का पति प्रकाश नंदेड़ा(35) निवासी मोती नगर ट्रेन में पॉपकॉर्न बेचते हैं। मंगलवार को दाहोद (गुजरात) से जम्मूतवी में चढ़े और रतलाम आ रहे थे। रास्ते में रावटी के पास अमरगढ़ और भैरोगढ़ के बीच ट्रेन में आइसक्रीम बेचने वाला दशरथ तीनों से विवाद करने लगा।

एक की हालत गंभीर

विवाद इतना बढ़ गया कि दशरथ ने तीनों पर चाकू से हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर तीनों भागे। चाकूबाजी से घटना से ट्रेन के डिब्बे में भगदड़ की स्थिति बन गई। रतलाम स्टेशन के प्लेटफॉर्म 5 पर ट्रेन रात 9.30 बजे पहुंची। घायलों को तुरंत एंबुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया। हालत ज्यादा गंभीर होने पर गोलू को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर किया।

महिला के साथ दुष्कर्म कर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

माही की गूंज, रतलाम।

रतलाम जिले के रावटी थाना इलाके में माही नदी पुलिया के नीचे 12 जून को एक महिला का शव मिला था। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और जब वह विरोध करने लगी तो हत्या कर दी।

महिला के पांच बच्चे हैं और उसके पति का निधन हो चुका है। आरोपित महिला की दूसरी शादी कराने के लिए ले गए थे। रिश्ता तय नहीं होने पर दोनों महिला के साथ वापस लौट रहे थे। रास्ते में शराब पीने के बाद आरोपितों ने सामूहिक दुष्कर्म किया।

विरोध के दौरान मारपीट भी की, जिससे महिला की मौत हो गई थी। इसके बाद वे शव को माही नदी की पुलिया के नीचे फेंक आए थे। महिला का शव निर्वस्त्र हालत में मिला था और उसके हाथ गमछे से बंधे थे।

11 जून की रात आरोपितों के साथ गई थी

रतलाम एसपी राहुल लोढ़ा ने पुलिस कंट्रोल रूम पर आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में बताया कि 12 जून को ग्राम बोरपाड़ा निवासी मुकेश डामोर ने पुलिस की सूचना दी कि माही नदी पुलिया के नीचे अज्ञात महिला की निर्वस्त्र लाश पड़ी है और दोनों हाथ गमछे से बंधे हुए हैं।

उसकी शिनाख्त वालारुंडी थाना शिवगढ़ निवासी 35 वर्षीय महिला के रूप में हुई। पुलिस को महिला के स्वजन ने बताया था कि 11 जून की रात वह दो व्यक्तियों के साथ अपना मोबाइल लेकर गई थी। पीएम रिपोर्ट के बाद महिला के साथ दुष्कर्म एवं मारपीट में हत्या की जानकारी सामने आई।

पुलिस जांच के दौरान 22 वर्षीय सुरेश पुत्र बारजी देवदा निवासी व 20 वर्षीय विदेश पुत्र मंगू दोनों निवासी गुन्दी नाका थाना बाजना का नाम संदिग्ध के तौर पर सामने आया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने हत्या करना स्वीकार किया।

दो माह पहले हुई थी पहचान

पुलिस को आरोपितों ने पूछताछ में बताया कि उनकी महिला से करीब दो महीने पहले पहचान हुई थी। महिला के पति की मौत हो चुकी है और उसके पांच बच्चे हैं। आरोपित उसकी दूसरी शादी कराने के लिए एक युवक के घर ले गए थे।

युवक की उम्र महिला से काफी कम होने के कारण उसके स्वजनों ने शादी के लिए मना कर दिया था। इसके बाद वापस लौटते समय रास्ते में बैठकर शराब पी। शराब पीने के बाद आरोपितों ने महिला के विरोध के बावजूद उसके साथ दुष्कर्म किया।

विरोध करने पर मारपीट के दौरान उसकी मौत हो गई। इस पर आरोपितों ने महिला के हाथ बांधकर शव माही नदी में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपितों से महिला का मोबाइल, कपड़े आदि जब्त किए हैं।

आपातकाल की 50 वीं बरसी पर मीसा बंदियों को किया सम्मानित

माही की गूंज, मंदसौर।

भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय मंदसौर में आपातकाल की 50 वीं बरसी पर मीसाबंदियों को मुख्य वक्ता सोनू गेहलोत, राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, भाजपा जिलाध्यक्ष नानालाल अटोलिया, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया द्वारा लोकतंत्र प्रहरी यों का सम्मान कर उनके संस्मरण सुने गये।

कार्यक्रम का शुभारंभ पं. दीनदयाल उपाध्याय जी एंव डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। तत्पश्चात लोकतंत्र प्रहरी संघ के सम्मानित सदस्यों का शॉल, माला और श्रीफल भेंट कर मंचस्थ अतिथि गणों द्वारा सम्मान किया गया।

इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सोनू गेहलोत ने संबोधित करते हुए कहा कि, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता कल संसद में संविधान की प्रति हाथ में लेकर पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान और लोकतंत्र को बचाने का कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने झूठा प्रचार-प्रसार किया। हकीकत में कांग्रेस राज में 100 से ज्यादा बार संविधान में संशोधन किया गया। जब 1975 में आज के दिन रात को 2 बजे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी उस समय सोनिया गांधी बहू के नाते वहां पर मौजूद थी। तब सोनिया गांधी ने संविधान बचाने की बात नहीं की,लेकिन कल जब संसद भवन पहुंचीं तो उनके हाथ में संविधान की प्रति थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व संविधान को कोई खतरा नहीं है।

कार्यक्रम का संचालन देवेंद्र मरच्या ने किया एंव आभार पुलकित पटवा ने माना। इस अवसर पर भाजपा जिला पदाधिकारीगण, मंडल अध्यक्ष गण, मंडल पदाधिकारीगण, मोर्चा जिलाध्यक्ष महामंत्री गण, नपा. पार्षदगण सहित कार्यकर्ता गण उपस्थित थे।

इनका हुआ सम्मान

कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानी हंसराज कबाडी, गोपाल पटवा, मनोहर लाल जैन, सुरेंद्र सिंह खेड़ा, ओमप्रकाश बिलोरिया, अम्बालाल गहलोत, नारायण सिंह चौहान, श्रीमती तुलसी मामा, श्रीमती पार्वती राधेश्याम काला, बलवंत फांफरिया, सुरेश अरवेंदकर, नरेश चंदवानी, देवेन्द्र मरच्या सहित अनेक मिसांबधियों तथा उनके परिवारजनों का सम्मान किया गया।

कस्टम ज्वेलरी निर्माण प्रशिक्षण का समापन

माही की गूंज, शाजापुर।

बैंक ऑफ़ इंडिया ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान शाजापुर द्वारा एन.आर.एल.एम. के सहयोग से ग्राम चित्तोड़ापूरा में आयोजित 13 दिवसीय कस्टम ज्वेलरी प्रशिक्षण का आज समापन किया गया। प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने वाले प्रशिक्षणार्थियों का असेसर स्वामिनाथ द्वारा मूल्यांकन लिखित, मौखिक व प्रयोगिक कार्य करवाकर किया गया। प्रशिक्षण में ग्रामीण क्षेत्र की 32 स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा प्रतिभाग कर विभिन्न प्रकार के कलात्मक आभूषण (चूड़ी, कंगन, हार सेट बेंगल बॉक्स इत्यादि) बनाये गए। इस अवसर पर मध्य प्रदेश डे. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला प्रबंधक कौशल बलवंत शितोले, आरसेटी निदेशक मुकेश गहलोत, समस्त आरसेटी स्टाफ एवं समस्त प्रशिक्षणार्थीगण उपस्थित थे।

आरसेटी निदेशक मुकेश गहलोत ने बताया कि, 29 जून 2024 से आरसेटी संस्थान में 30 दिवसीय ब्यूटी पार्लर एवं महिला सिलाई का आवासीय प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के इच्छुक महिलाऐं जिनकी उम्र 18 से 45 वर्ष है वे अपना पंजीयन करवाकर निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते है।

विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में सीएम राइज विनोबा हायर सेकेंडरी स्कूल का चयन

माही की गूंज, रतलाम।

रतलाम के सीएम राइज विनोबा हायर सेकेंडरी स्कूल का चयन विश्व के सर्वश्रेष्ठ दस स्कूलों में होने पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप ने मंगलवार को मंत्रालय वल्लभ भवन में स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह को बधाई दी और गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया।

जानकारी देते हुए मंत्री काश्यप ने स्कूल शिक्षा मंत्री को बताया कि, विश्व के प्रतिष्ठित इस पुरस्कार के लिये विनोबा हायर सेकेंडरी स्कूल का चयन नवाचार (इनोवेशन केटेगरी) श्रेणी में हुआ है। चयन से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविदों ने नवाचार के क्षेत्र में स्कूल में किये जा रहे कार्यों पर उप प्राचार्य गजेन्द्र सिंह राठौर का ऑनलाइन इंटरव्यू भी लिया।

मंत्री काश्यप ने बताया कि, इस स्कूल में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिये पिछले दो वर्षों से कई तरह के नवाचार हो रहे हैं। टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत साइकल ऑफ ग्रोथ के माध्यम से शिक्षकों को बदलाव के वाहक के रूप में लाया गया। स्कूल लीडर्स के मार्गदर्शन में ज्वॉयफुल लर्निंग द्वारा विद्यार्थियों और पालकों को जोड़ा गया। परिणाम यह हुआ कि स्कूल के 577 में से 545 विद्यार्थी किसी न किसी रूप में कई गतिविधियों से वर्ष भर जुड़े रहते हैं। स्कूल में टीचिंग-लर्निंग मटेरियल, प्रिंट रिच, स्टूडेंट डायरी, टीचर्स डायरी, हूक बैंक, मार्निंग मीटिंग, सर्कल टाइम, एकेडमिक संवाद और बिहेवियर मैनेजमेंट जैसे कई उपक्रम किये जाते हैं।

उल्लेखनीय है कि, पिछले दिनों यूएसए की प्रतिष्ठित संस्था टी फॉर एजुकेशन ने सौ देशों के दस हजार स्कूलों में से जिन दस स्कूलों का चयन ÷द वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल प्राइज'' के लिये किया है, उसमें रतलाम के सीएम राइज विनोबा हायर सेकेंडरी स्कूल का चौथा स्थान है।

प्री मानसून की झमाझम बारिश के बाद अन्नदाता लगे खरीफ फसल की बोवनी में

माही की गूंज, उज्जैन/रुनीजा।

अभी मध्यप्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रीय नहीं हुआ है तथा मानसून की बारिश का दौर भी प्रारंभ नहीं हुई है लेकिन मानसून के पूर्व कही कही प्री मानसून की अच्छी व झमाझम बारिश होने के बाद भी गर्मी से राहत नही मिल रही है। अभी भी कूलर पंखे दिन में व रात में चलाना पढ़ रहे है। गत 21 जून शुक्रवार रुनीजा क्षेत्र में लगातार 6 से 7 घण्टे की बारिश रुनीजा, माधवपुरा, गजनीखेड़ी तथा आसपास ग्रामो में अन्नदाता खरीफ फसल की बुवाई में लग चुके हैं। बुधवार तक क्षेत्र के अधिकांश किसान सोयाबीन की बोवनी को लेकर व व्यस्त हो गए। कहीं-कही अन्नदाता खाद व दवाई मिलाकर बीच उपचार करते नजर आए तो कहीं ट्रैक्टरों पर बीज की बोरियां रख कर खेतों की ओर चल पड़े। सुबह से लगाकर शाम तक क्षेत्र में मौसम खुला रहने से जीन खेतो में पानी नही भरा वहां बोवनी भी अच्छी हुई।

इस संदर्भ में विश्वजीत सिंह राठौर ने बताया कि, 20 से 25 दिन पहले से ही खेत पूरी तरह खरीफ फसल सोयाबीन की बोनी के लिए तैयार कर लिए थे। बस बारिश का इंतजार था और अभी अच्छी बारिश होने के बाद सोयाबीन की बोवनी का कार्य पूरा हो गया है। माधवपुरा के प्रगतिशील किसान व कृषक मित्र सतीश नागर ने

बताया कि, क्षेत्र में अच्छी बारिश होने से सभी किसान भाई सोयाबीन की बोवनी के कार्य में जुट गए हैं। 22 जून से प्रारंभ हुई बोवनी लगभग अपने अंतिम चरण पर चल रही है क्षेत्र में 85 से 90 फीसदी तक सोयाबीन की बोवनी का कार्य हो चुका है। साथ ही रात को झमाझम बारिश से बोवनी को लाभदायक बना दिया है कुछ किसानों से चर्चा करने पर पाया कि 90 फीसदी जमीन पर सोयाबीन के विभिन्न वैरायटी लगाई गई हैं। इस बार नई वैरियटयों की ओर किसानों का रुख अधिक रहा है मुख्य रूप से जेइस 1135, जेएस 1569, 2024, 2034 ब्लैकबोर्ड की बोनी अधिक की गई है। बाजार से बीच खरीदने के बजाय किसान खुद का बीच तैयार करने में अधिक विश्वास रखता है और पहले से ही उसका अंकुरण परीक्षण कर बीज उपचार दवाई से उपचारित कर तैयार कर लिया जाता है ताकि बोते समय समय की बचत सके। विगत कुछ वर्षों से बेलों से होने वाली खेती समाप्त हो गई है। सारे कार्य कृषि यंत्रों व ट्रेक्टर से हो रहे है। जिन किसानों के पास खुद का ट्रैक्टर हैं उन्होंने दो दिन में ही अपनी सोयाबीन की बोवनी समाप्त कर ली तथा जिनके पास स्वयं का साधन नहीं है वह 700 रुपए प्रति घण्टे से भाड़े के ट्रैक्टर से बोवनी कार्य करवा रहे है। इस बार पर्याप्त बारिश होने की वजह से लगता है 100 फीसदी बोवनी सफल हो जाएगी परंतु परिणाम तो 5 दिन बाद ही सामने आएंगे।

कृषि विस्तार अधिकारी रुनीजा शानू पांडेय ने बताया कि, 24 जून तक बडनगर में 3.38 इंच या 86 एम एम बारिश हो चुकी हैं और आने वाले हफ्ते में मौसमी बारिश अच्छे स्तर पर हो जाएगी। मौसम को देखते हुए किसान भाई अब बोनी कर सकते है।

गिड़गिड़ाता रहा दलित युवक, नंगा कर बेल्ट से पीटते रहे हैवान

छतरपुर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक दलित युवक को बंधक बनाकर निर्वस्त्र कर मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना 21 जून की है जब एक दलित युवक अपना रेस्टोरेंट बंद कर देर रात पैदल ही अपने घर आ रहा था। बताया जा रहा है कि रास्ते में 3 से 4 लोगों ने कट्टे की नोक पर उनका अपहरण कर लिया और शहर से दूर लेकर जाकर उसके कपड़े उतार कर नग्न अवस्था में कट्टे की बट और बेल्टों से मारपीट शुरू कर दी। लगभग एक घंटे मारपीट करने के बाद उसे रात में निर्वस्त वहां से भगा दिया गया। खून से लथपथ युवक ने वहां से भाग कर एंबुलेंस बुलाई और अस्पताल पहुंच गया। जहां वह 4 दिनों तक भर्ती रहा और उसका इलाज चलता रहा।

दलित युवक को बंधक बनाकर मारपीट करने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में फरियादी युवक के साथ मारपीट करते हुए 3 से 4 लड़के दिखाई दे रहे हैं। सभी के हाथों में अवैध हथियार दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित दलित युवक पिटाई कर रहे बदमाशों के हाथ-पैर जोड़ता रहा लेकिन आरोपी उसे गाली देते हुए मारते रहे और उसके कपड़े उतार दिए।

इधर सोशल मिडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस सख्त है और तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक मुख्य आरोपी देवा को गिरफ्तार कर अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। छतरपुर एसपी अगम जैन ने बताया की फरियादी युवक के बताए अनुसार और वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जल्द सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। पुलिस मामले को लेकर बेहद सख्त है।

नगर पालिका द्वारा ने चलाया विशेष अभियान

माही की गूंज, खरगोन।

शासन के निर्देशानुसार नगर पालिका परिषद खरगोन द्वारा मुख्य पालिका अधिकारी श्री एमआर निगवाल द्वारा पुरी टीम को निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को तत्काल हटाने के आदेश दिए और मुहिम चलाई गई। जिसमें स्वास्थ्य अधिकारी अमित डामोर द्वारा अपनी टीम के साथ समस्त नगर में सीएंडडी वेस्ट हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत शहर में जगह जगह से सीएंडडी वेस्ट को भरकर सीएंडडी कलेक्शन सेंटर पहुंचाया गया। साथ ही जिसके मकान एवं होटल, दुकानों के सामने सीएंडडी वेस्ट पाया गया वहा स्पॉट फाइन किया गया और समझाइश दी गई कि अगर आपके पास सीएंडडी वेस्ट निकलता है तो इसे रोड़ पर खुला न फेंके।

नगर पालिका परिषद खरगोन द्वारा सीएंडडी संग्रहण वाहन संचालित किया जा रहा है। नपा को हेल्पलाइन नंबर 14420 पर सहायता के लिए सूचना करे एवं अपने सीएंडडी वेस्ट को नगर पालिका परिषद खरगोन सीएंडडी के वाहन में भरवा कर सुरक्षित कलेक्शन सेन्टर में पहुंचाए। शहर को गंदा न होने दे। अभियान के अंतर्गत 5.62 टन सीएंडडी वेस्ट संग्रहण किया गया एवं 2200 रुपये का स्पॉट फाइन किया गया। अभियान में स्वच्छता निरीक्षक सुभाष रघुवंशी, दरोगा सूरज धारीवाल, अय्यूब खान एवं आईईसी टीम सदस्य उपस्थित रहे।

मॉनिटरिंग समिति की बैठक संपन्न

माही की गूंज, खरगोन।

25 जून को कलेक्टर कर्मवीर शर्मा की अध्यक्षता में जिला सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागृह में आयोजित की गई। जिला सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति के सभी सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज अपराधों में दी जाने वाली राहत राशि एवं प्रकरणों की स्थिति एवं न्यायालय में प्रचलित प्रकरणों के बारे में कलेक्टर श्री शर्मा ने जानकारी प्राप्त की। समिति के सचिव एवं सहायक आयुक्त श्री प्रशांत ने जानकारी देते हुए बताया कि अनुसूचित जाति के 01 जनवरी से जून 24 तक कुल 123 प्रकरण राहत राशि के लिए प्राप्त हुए हैं। उक्त 123 प्रकरणों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। जिनमें से 34 प्रकरणों में 57.84 लाख रुपये का भुगतान संबंधितों को किया जा चुका है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के प्राप्त 124 प्रकरणों को स्वीकृत किया जाकर 34 प्रकरणों में भादवि की धाराओं के अनुसार 37.53 लाख रुपये की राशि का संबंधितों पीढितों को किया जा चुका है।

कलेक्टर श्री शर्मा ने जाति प्रमाण पत्र की वजह से लंबित प्रकरणों के संबंध में निर्देश दिए प्रकरणों की सूचि तैयार कर अपर कलेक्टर श्रीमती रेखा राठौर को उपलब्ध करवाए। श्रीमती राठौर उक्त प्राप्त सूची संबंधित एसडीएम को भेजकर तत्काल प्रमाण पत्र बनवाने की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करेंगे। जिससे प्रकरणों में विलंभ न हो। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती रेखा राठौर एवं श्री जेएस बघेल, एडिशनल एसपी तरूणेन्द्र सिंह बघेल, सहायक आयुक्त प्रशांत आर्या, जिला अभियोजन अधिकारी महेन्द्र भानुप्रिय, जिला खनिज अधिकारी सावन सिंह चौहान महिला एवं बाल विकास विभाग की सहायक संचालक सुश्री मोनिका बघेल, आजाक थाना प्रभारी उपस्थित रहे।

नेत्र रोगियों का किया परीक्षण

माही की गूंज, बड़वानी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सुरेखा जमरे और सिविल सर्जन डॉ अनिता सिंगारे के मार्गदर्शन में लायंस क्लब बड़वानी सिटी एवं ज़िला चिकित्सालय बड़वानी के संयुक्त तत्वावधान में 26 जून को निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़वानी ओर आसपास के जिलों से लगभग 170 नेत्र मरीज अपना ईलाज कराने आए। नेत्र विशेषज्ञ डॉ आशीष सेन और नेत्र सहायक रविंद्र टेकाम, नेत्र सहायक अनिल राठौड़, श्री भावसार तथा आयुष डॉक्टर्स की टीम ने मरीजों का परिक्षण किया । लायन सुधीर कुमार पांडे ने बताया कि इस शिविर में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 25 बच्चे भी जिले भर से आए जिनमें जन्मजात विभिन्न नेत्र संबंधित बीमारी थी। उन बच्चों में से 12 बच्चों को भी ईलाज के लिए इंदौर चोइथराम नेत्रालय भेजा गया है। नेत्र शिविर संयोजक लायन महेश चन्द्र शर्मा ने कहा कि मोतियाबिंद के मरीजों को ऑपरेशन के लिए चोइथराम नेत्र चिकित्सालय इंदौर भेजा गया है। इन 20 मरीजों को निःशुल्क लैंस प्रत्यारोपण किया जाएगा। साथ ही नेत्र शिविर में आए 12 बच्चों का भी निःशुल्क ईलाज राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत किया जाएगा। कुछ बच्चों में भी मोतियाबिंद के लक्षण पाए गए तथा नेत्र की अन्य बीमारी भी होने से ईलाज हेतु भेजा गया है। भेजे गए सबसे छोटा बच्चा 14 माह का और 16 वर्ष तक के बच्चे भेजे गए हैं। 13 बच्चों के पेपर्स पूरे नहीं होने से इंदौर नहीं भेजे जा सके है। उन बच्चों को अगले महीने लगने वाले शिविर में बुलाया गया है।

आवारा कुत्तों को पकड़ने चलाया अभियान

माही की गूंज, खरगोन।

शहर में गत दिवस हुई घटना जैसे ही कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के संज्ञान में आयी तो उन्होंने नगर पालिका सीएमओ को तत्काल शहर में घुम रहे आवारा कुत्तों को पकड़ने एवं उन्हें शहर से दूर अन्य स्थान पर ले जाकर छोड़ने के निर्देश दिए। जिससे इस प्रकार की घटनाओं की पूनरावृत्ती न हो। उक्त निर्देशों के पालन में 25 जून को नगर पालिका खरगोन की टीम द्वारा रात भर विशेष अभियान चलाकर शहर की कॉलोनियो में घुम रहे आवारा कुत्तों का पकड़ कर शहर से दूर अन्य स्थानों पर ले जाकर छोड़ा गया।

अंतराष्ट्रीय नशा निवारण दिवस का हुआ आयोजन, दिलाई गई शपथ

माही की गूंज, खरगोन।

नशामुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जिले में 26 जून को नशीले पदार्थों के दुरूपयोग एवं अवैध व्यापार के विरूद्ध अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत मद्यपान तथा मादक पदार्थों, नशीली दवाईयां, शराब एवं विभिन्न प्रकार के नशे से होने वाले दुष्परिणामों से समाज, युवाओं को अवगत कराने, नशामुक्ति के लिये जनजागृति एवं शपथ के विभिन्न कार्यक्रम जैसे रैली, नुक्कड नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशालाओं के आयोजन होंगे। उक्त नशा निवारण दिवस के आयोजन हेतु प्रभारी अधिकारी एवं संयुक्त कलेक्टर श्रीमती हेमलता सोलंकी ने विभिन्न विभगों सहित धार्मिक संस्थाएं प्रजापिता ब्रम्हाकुमारी, गायत्री परिवार एवं सामाजिक संस्थाओं को पत्र लिखकर कार्यक्रम के आयोजन एवं जनजागृति के लिए कार्य करने हेतु कहा है।

माही की गूंज, खण्डवा।

अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर श्री दादाजी धूनीवाले जिला चिकित्सालय खंडवा में मरीजों, उनके परिजनों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रभारी सिविल सर्जन डॉ. संजीव दीक्षित ने नशा न करने की शपथ दिलवाई तथा कार्यक्रम के नोडल अधिकारी द्वारा शपथ का वाचन किया गया। इस दौरान बताया गया कि देश की चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त प्रदेश अभियान के अंतर्गत एक जुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल स्वयं को बल्कि समुदाय, परिवार मित्रों को भी नशा मुक्त कराएंगे। हम अपने प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करेंगे। इस अवसर पर आर.एम.ओ. डॉ. एम.एल. कलमे, डॉ. नितिन कपूर, डॉ. आदित्य जाधव सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

कही भी जर्जर भवन में कक्षा संचालित न हो- सीईओ

माही की गूंज, धार।

जिले में कही भी जर्जर भवन में कक्षा संचालित न हो। बच्चों के छात्रवृत्ति के कार्य को सभी बीईओ देखे । स्कूल भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कार्यवाही करें। यह निर्देश सीईओ जिला पंचायत सविता झानिया ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में दिए।

उन्होंने कहा कि आवास सहायता योजना में बच्चों को परेशानी न आए। बैठक में बच्चों के ऐडमिशन , गणवेश, साइकिल वितरण, बालक-बालिका छात्रावास, छात्रावास में शौचालय की स्थति पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में सहायक आयुक्त ब्रजकांत शुक्ला, सभी बीईओ, बीआरसी , कॉलेज के प्राचार्य व सम्बन्धित आधिकारी मौजूद थे।

बच्चों को मोबाइल का अधिक संचालन ना करने दें

माही की गूंज, खरगोन।

राष्ट्रीय विधिक साक्षरता शिविर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुनील कुमार जैन के निर्देश एवं सचिव जिला न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह के मार्गदर्शन में लिगल एड डिफेंस कॉउंसिल सिस्टम के डिफ्टी चीफ रूपेश शर्मा, सहायक सुश्री निशा कौशल द्वारा ग्राम लाडवी में शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनांगत तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए साक्षरता शिविर एवं बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके सरक्षण के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। लिगल एड डिफेंस कॉउंसिल के डिफ्टी चीफ ने बताया कि तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण सहित बाल तस्करी जैसी गंभीर गतिविधियां दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है और यह गम्भीर आपराधिक गतिविधियों में से एक है। जिसमें बच्चो ओर लड़कियों की तस्करी बड़े पैमाने पर एक देश से दूसरे देश मे भेजा जाता है। तस्करी में जिन बच्चों और लड़कियों को लाया जाता है उन्हें फिर वहां पर खरीद ओर बेचा जाता है और उन बच्चों व लड़कियों से अवैध काम करवाया जाता है। भीख मंगवाना, गंभीर अपराध में लिप्त करवाना, वैश्यावर्त्ति करवाना ऐसे गलत काम करवाया जाता है।

तस्करी कई प्रकार की होती है जैसे नशीली दवाइयों, वैश्यावर्त्ति, मानव तस्करी, अपहरण जैसी बहुत सी होती है। इन्हीं गम्भीर अपराधों को देखते हुये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व्दारा योजना 2015 बनाई गई। जिसमें इन मामलों में पीड़ितों के लिए कई प्रकार की सहायता के लिए योजनाएं संचालित की गई है। पुनर्वास, प्रतिकर विधिक सहायता जैसी सहायता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व्दारा पीड़ितों को प्रदान की जाती है। लिगल एड डिफेंस कॉउंसिल की सहायक सुश्री निशा कौशल ने बच्चो को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाए ओर उनके सरक्षण के सम्बध्द में बताया कि प्रत्येक बच्चो को उनके मूलभूत अधिकार प्राप्त है। उन्हें जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, सरक्षण का अधिकार और समाज में भागीदारी का अधिकार भी शामिल है। प्रत्येक बच्चों को उनके विधिक अधिकार के संबंध में सूचित करने के अतिरिक्त विधिक सशक्तीकरण के लिए सहयोगी बने तथा विधिक सेवा प्रदाताओं के साथ असरदायक कार्यवाही और अच्छे संबंध बनाने के लिए समस्त जनता और धार्मिक संगठनों से भी जोड़ना इस योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बच्चो को मोबाइल का अधिक संचालन ना करने दे। घर के वरिष्ठ की उपस्थिति में ही मोबाइल चलाये। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा ऐसे मामलों में पीड़ितों को बहुत सी सुविधाएं प्रदान की गई है।

स्कूल की प्राचार्य मधुबाला डावर ने बच्चों को समझाइश दी कि किसी भी अनजान व्यक्ति से बातचीत न करे। कोई खाने पीने को दे तो कुछ खाये नहीं। घर पर बडे बुजुर्गों का सम्मान करें और बड़ों का कहना मानना चाहिए। स्कूल में अनुशासन में रहकर अपने गुरु या अध्यापकों का सम्मान करें। स्कूल की अध्यापिका कविता जायसवाल ने कार्यक्रम का संचालन किया। ज्योति कुशवाहा ने कार्यक्रम का आभार माना।

नपा अध्यक्ष ने कर्मचारियों की ली क्लास, साफ-सफाई को लेकर लगाई फटकार

माही की गूंज, अलीराजपुर।

स्थानीय नगर पालिका अध्यक्ष एवं जोबट विधायक सेना महेश पटेल ने नपा अधिकारी-कर्मचारी ओर स्टॉफ की बैठक ली। बैठक मे नपा अध्यक्ष श्रीमती पटेल ने नगर के विभिन्न वार्डो मे पसरी गंदगी, साफ-सफाई को लेकर सफाई प्रभारी, दरोगा ओर कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि, नगर की साफ-सफाई के मामले मे लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, मुझे शिकायत मिली तो त्वरित कार्रवाई की जाएंगी। स्वच्छता मे किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। जो नालिया चाक पड़ी हे, उसे दुरुस्त कर सुचारु रूप से चालू करे। उन्होंने बैठक मे सभी कर्मचारियों को निर्देश दिए की समय पर कार्यालय पहुंचकर आमजनों की समस्याओं का निराकरण करे, अगर कोई परेशानी आती हे तो मुझे अवगत कराएं। इस दोरान उन्होंने नपा की विभिन्न शाखाओ की समीक्षा करते हुए कहा कि, सभी लंबित कार्यों को तत्परता से निपटाए। नपा अध्यक्ष ने कहा की वार्ड पार्षद अपने-अपने वार्डो मे घूमकर जायजा ले ओर समस्याए हल करवाए। उन्होंने कहा की वह खुद सप्ताह मे एक बार नपा मे नगर की समस्याओ ओर साफ-सफाई की समीक्षा बैठक लेंगी व लापरवाही ओर कोताही बरतने वाले कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर नपा सीएमओ कमल मुजल्दा, उपयंत्री, पार्षद राजू शाह, पार्षद पति संतोष थेपड़िया, सचिन राठौड़, अजहर चंदेरी, ईमरान खत्री, रितेश राठौड़, पिंटू राठौड़ सहित नपा कर्मचारीगण मौजूद थे।

विधायक सेना पटेल ने की विभागों की समीक्षा, अनियमित्ता के चलते लगाई फटकार

माही की गूंज, च.शे. आजाद नगर।

जनपद पंचायत सभा कक्ष में विधायक सेना महेश पटेल ने सभी विभागों की समीक्षा की। जिसमें जनपद पंचायत सीईओ, बीईओ सहित सम्बन्धित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। विधायक सेना पटेल ने सबंधित अधिकारी से उनके विभाग में विकास कार्य को लेकर जानकारी मांगी जिसमें शिक्षा विभाग, पीएचई विभाग में कुछ अनियमित्ताओं के चलते संबंधित अधिकारी को फटकार लगाई और आगे से कोई भी शासन के द्वारा चलाई जा रही योजनाओ में त्रुटी न हो उसकी समझाइश दी। विधायक सेना पटेल ने बेठक के दोरान कहा कि, ब्लाक में प्रत्येक नागरिक को सरकार की योजना का लाभ दिया जाए और जो बाकी रह गए उनको अतिशीघ्र पूर्ण किया जाए। साथ ही स्कूल में मध्यान भोजन में भरी मात्रा में ला परवाई बरती जा रही जो की आपकी जवाबदेही है उसे भी ठीक करे। जो समूह संचालित नही कर पा रहा उस पर भी कारवाई की जाए नही तो में स्वयं आपके ऊपर कार्यवाही करने व विधानसभा में मुद्दा उठाएगी। साथ ही राशन की दुकानों में भी अनियमित्ता बरती जा रही गरीब किसान 4 से 6 महीना से घूम रहे लेकिन आप कालाबाजारी कर उन्हे राशन समय पर दे नही रहे उस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। नल जल योजना जो की कागजी कार्यवाही में चल रही जमीनी हकीकत कुछ और ही हे पूरे प्रदेश में यह मुद्दा उठ रहा की उसमे बहुत ही ज्यादा ला परवाही बरती जा रही जिससे जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही विधायक ने सेजावाडा अस्पताल में बिजली ओर पानी नहीं होने की जानकारी के चलते सेना पटेल ने अपनी विधायक निधि से डीपी व बिजली के खंबे पानी की व्यवस्था के लिए विधायक निधि से राशी स्वीकृति करने की बात भी कही। साथ ही नगर पंचायत पहुंची जहा सेना पटेल ने सीएमओ के नहीं मिलने पर नाराजगी जताई जो भाबरा भुरा घाटा आबादी में आरओ का पानी नहीं पहुंचने को लेकर नगर पंचायत सेना पटेल पहुंची थी। साथ ही हाईटेंशन बिजली के तार भाबरा वार्ड क्रमांक 8-9 में मकानों के ऊपर से गुजरने को लेकर बिजली विभाग के अधिकारी से चर्चा कर उसे हटाने की बात कही। साथ ही जनपत अध्यक्ष इंदरसिंह डावर ने भी सम्बोधित अधिकारीयों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को गरीब तबके तक पहुंचाने को लेकर कहा।

इस दौरान बैठक में जनपत समीक्षा बैठक में जनपत अध्यक्ष इन्दरसिंह डावर, मदन डावर, हरिश भाबर, राजेश जेन, मंयक सोनी, जनपत सीईओ वेरसिह मुजाल्दा, बीईओ विनोद कुमार कोरी, बीआरसी राजेन्द्र बेरागी, सहित स्वास्थ विभाग, महिला बाल विकास विभाग, पीएचई विभाग, पंचायत विभाग, राजस्व विभाग, आरईएस विभाग, खाद्य विभाग, पशु-चिकित्सक विभाग आदि विभाग के कर्मचारी व अधिकारी मौजूद थे।

ग्रीन सिटी-क्लीन सिटी अभियान के तहत किया पौधारोपण

माही की गूंज, अलीराजपुर।

ग्रीन सिटी-क्लीन सिटी अलीराजपुर अभियान के तहत नगर के ब्राह्मण समाजजनों ने खंडवा-बड़ौदा मार्ग स्थित परशुराम वाटिका में विभिन्न प्रजातियों के 51 पौधों का रोपण किया। पौधरोपण कार्यक्रम के संयोजक समाज के पूर्व अध्यक्ष आशुतोष पंचोली ने बताया कि, नगर को ग्रीन सिटी-क्लीन सिटी बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में नगर की सुरक्षित व रिक्त पड़ी ऐसी भूमि जिसका अन्य कोई कार्यों में उपयोग नहीं हो रहा है उन स्थानों पर पौधरोपण करने की योजना सहयोग संस्था द्वारा बनाई गई है। इसी के तहत परशुराम वाटिका में उक्त पधारोपण किया गया है। नगर के पर्यावरण को और अधिक सुंदर बनाने के लिए इस प्रकार का काम हरीतिमा संवर्धन के माध्यम से किया जा रहा है। पंचोली ने बताया कि, ग्रीन सिटी अभियान की योजना जब ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ सदस्यों को बताई गई, तब पूर्व अध्यक्ष अजय शर्मा ने इस संबंध में समाज जनों से चर्चा की और समाज के सदस्यों ने अपने दिवंगत परिजनों की स्मृति में पौधारोपण करने की सहमति दी।

धोखाधड़ी करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, 39 लाख 50 हजार रुपए नगद बरामद

माही की गूंज, बड़नगर।

उज्जैन के पास बड़नगर के व्यापारी से गेंहू खरीद कर धोखाधड़ी करने वाले गुजरात के पांच आरोपियों से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गेंहू के नाम पर की गई धोखाधड़ी का 39 लाख 50 हजार रुपए केश भी आरोपियों से बरामद किया है। बड़नगर के संजना पार्क में रहने वाले अनाज व्यापारी जितेंद्र मारु ने 22 मई को बड़नगर थाने में शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसमें उसने बताया था कि, अपने आप को गुजरात के बड़े व्यापारी के साथ संबंध बताने वाले जयेश सिंधी तथा विनोद हरयाणी के द्वारा फोन पर सम्पर्क हुआ उन्होंने गेहूँ की आवश्यकता बताते हुए अलग अलग फर्म के नाम पर दिनांक 5 अप्रेल से लेकर 26 अप्रेल 2 हजार 24 तक ऑर्डर देकर कुल 10 ट्रक गेहूँ खरीदे। उक्त 10 ट्रक गेहूँ में से आरोपियों के द्वारा 3 ट्रक गेहूँ का भुगतान किया गया तथा शेष 7 ट्रक गेहूँ के रुपए की मांग की जाने पर आरोपियों के द्वारा आनाकानी की गयी तथा अपना फोन बंद कर लिया गया। बाद में फरियादी जितेंद्र अपनी राशि लेने लिए आरोपियों के देहगाँव, जिला गांधीनगर, गुजरात स्थित में ऑफिस व गोदाम को चैक करने गए तो ऑफिस बंद पाये गये। जितेंद्र ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी को लेकर आरोपियों के खिलाफ थाना बडनगर में धारा 406, 420, 467, 468, 471 में एफआईआर दर्ज कराई।

पुलिस विवेचना में आरोपी जयेश पिता ताराचंद्र सिंधी उम्र 62 वर्ष निवासी हिम्मत नगर जिला साबरकाठा गुजरात, विनोद हरयाणी पिता जगदीश भाई उम्र 39 वर्ष निवासी देहगाँव जिला गांधीनगर गुजरात, भावेश पिता प्रकाश सिंधी उम्र 30 वर्ष निवासी कराई चौकडी नाना चिरौडा जिला अहमदाबाद गुजरात, पंकज पिता तोलाराम जैन उम्र 48 वर्ष निवासी कठवाडा नारोडा जिला अहमदाबाद एवं धीरू भाई पिता दाया भाई उम्र 60 वर्ष निवासी बापा नगर अहमदाबाद गुजरात को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 7 ट्रक गेंहू के नगदी 39 लाख 50 हजार रूपए जप्त किए गए है।

धमकी देकर अवैध वसुली करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

माही की गूंज, बड़नगर।

संग्राम पिता प्रहलाद वैरागी निवासी ग्राम कजलाना हा.मु. टोरंटो कालोनी बडनगर द्वारा फरियादी को डरा धमका कर अवैध रुप से पैसो की मांग कर जान से मारने की धमकी दी गई। जिस पर बडनगर पुलिस द्वारा आरोपी संग्राम बैरागी के खिलाफ अपराध क्रमांक 247/2024 धारा भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। पुलिस को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि, उक्त आरोपी को टोरंटो कालोनी बडनगर में देखा गया है। बाद सूचना के आरोपी की गिरफ्तारी हेतू टीम गठीत कर आरोपी संग्राम बैरागी को टोरंटो कालोनी से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। उक्त आरोपी के खिलाफ थाना मे 5 अपराध पंजीबध्द है। उक्त कार्रवाई में निरीक्षक अशोक कुमार पाटीदार, उनि सोभाग सिंह, सउनि नरेन्द्र भुरिया, प्र.आर. नरेन्द्र सिंह परिहार, आर. मुकेश, आर. संदीप, सैनिक गोविंद सिंह परिहार की भुमिका रही।

रेल लाओ संघर्ष समिति ने सांसद एवं वन मंत्री को सौंपा ज्ञापन

माही की गूंज, अलीराजपुर।

क्षेत्र में लम्बे समय से सक्रीय रूप से कार्यरत छोटा उदयपुर-धार रेल लाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने गत दिनो रतलाम-झाबुआ संसदीय क्षेत्र की नवनिर्वाचित सांसद अनिता चौहान एवं म.प्र. शासन के वन मंत्री नागरसिंह चौहान से मुलाकात कर उनका स्वागत अभिनंदन किया, साथ ही क्षेत्र में रेल्वे संबंधी समस्याओं के निराकरण एवं अन्य बहुप्रतिक्षित विकासमूलक मांग समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंप कर समस्याओं का निराकरण करने का अनुरोध किया। भारत सरकार के केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव के नाम से सौंपे गये ज्ञापन में समिति के सदस्यों उन्हें अवगतत कराया कि, दाहोद-खंडवा नवीन रेलवे लाइन की स्वीकृति हेतु केंद्रीय रेल मंत्री से अपने दिल्ली प्रवास के दौरान मिलकर मांग को अलीराजपुर -धार -बड़वानी- खरगोन- खंडवा जनजाति आदिवासी बहुल रेल विहिन् पिछड़े क्षेत्र के विकास तथा जनता को सस्ती आवागमन सुविधा प्रदान करने हेतु इस अति आवश्यक मांग को शीघ्र पूरा करने हेतु स्वीकृत करवाने का आग्रह किया है।

मानसून की पहली बारिश से खिले किसानों के चहरे

माही की गूंज, बरझर।

बरझर में बरसात की पहली बारिश ने किसानों के चहरे खिला दिए हैं। रविवार देर शाम करीब 6 बजे बरसात का दौर चालू हुआ जो सोमवार सुबह 7 बजे तक चालू था। सोमवार से किसान अपने खेतों में हलबखर लेकर जुताई में लग गए है। प्रदेश में मानसून की बारिश प्रारम्भ हो गई है इस क्षेत्र में खासकर बारिश के मौसम में मक्का व कपास की खेती अधिकांश की जाती है। पथरीली जमीन पर उड़द की खेती करते हैं। क्षेत्र में पहली बारिश होने से किसानों के चहरे खिलें है वही हेडपंप व पानी बोर का जल स्तर भी कम होने लगा था ऐसे में ग्रामीण जनों ने पेयजल के लिए भी राहत की सांस ली है। साथ ही गर्मी की तपन से भी खासे परेशान थे जिससे भी अब निजात मिलेगी।

तूफान लेकर हवा हुए अज्ञात बदमाशो का 16 दिन बाद भी कोई सुराग नही

लगातार जगह-जगह फुटेज खंगाल रही पुलिस टीम और तूफान मालिक की टीम को मिली निराशा

माही की गूंज, उज्जैन। विजय सोलंकी

भाटपचलाना थाना अंतर्गत रुनीजा में संचालित ओएसिस एकेडमी विद्यालय परिसर में बसों के साथ खड़ी विद्यालय की तूफान गाड़ी क्रमांक एमपी 13 बीए 4165 को 8 जून को सुबह 4 बजे के लगभग बाइक से आए बदमाश तूफान लेकर हवा हो गए। सुबह विद्यालय की टीम विद्यालय परिसर पहुची और सर्वे के लिए जाने के लिए तूफान गाड़ी को देखा तो पता चला कि, तूफान गाड़ी तो यहां से ला पता हो गई है। इस पर तत्काल ड्राइवर को बुलाकर उससे बात की तथा विद्यालय परिसर में सो रहे चौकीदार परिवार से भी चर्चा की। चौकीदार परिवार की महिला ने बताया कि, सुबह गाड़ी यही खड़ी थी 3 बजे से 4 बजे के बीच में जब बारिश प्रारंभ हुई तो परिसर से उठकर चौकीदार परिवार जैसे ही घर में जाकर सोया और मौके की तलाश में बैठे बदमाश 4 बजे तूफान गाड़ी लेकर विद्यालय परिसर से रफू चक्कर हो गए। उक्त तूफान के लापाता होने की जानकारी विद्यालय परिवार के स्टाफ ने संचालक गौरव वैष्णव और अक्षत वैष्णव को दी। उसके बाद विधायलय कि टीम संचालक व इनके मित्रों ने अपने-अपने स्तर पर गाड़ी की तलाश प्रारंभ की 4 बजकर 1 मिनिट पर रुनीजा के बालाजी पेट्रोल पम्प के ऑफिस पर उक्त तूफान रतलाम रोड की तरफ जाती हुई देखी। उसके बाद उक्त घटना की जानकारी भाटपचलाना थाने पर दी।

थाना प्रभारी आनन्द भाबोर ने तत्काल दो अलग-अलग टीम एएसआई वरसिंह चरपोटा, एएसआई कन्हैयालाल मचार, नवीन जादम प्रधान आरक्षक रामनारायण चोहान को गाड़ी की तलाश में रवाना किया। पुलिस टीम के सदस्य, विद्यालय संचालक परिवार रतलाम रोड तरफ गाड़ी की तलाश में निकला। सातरूंडा पुलिस चौकी पर लगे सीसी कैमरे के फुटेज में गाड़ी रतलाम तरफ जाती दिखाई। लेकिन बदमाशो ने बिलपांक टोल टैक्स पार नही किया इस बीच पुलिस की एक टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण किया तो पुलिस को बस के पीछे होंडा कंपनी की बाइक एमपी 09 एनसी 9733 व कुछ चिप्स रैपर पड़े मिले। ऐसा लगता है कि बदमाश मौके की तलाश में ही बैठे थे और जैसे ही 3 से 4 बजे के बीच बारिश होने लगी चौकीदार परिवार उठकर गया और बदमाशो ने मौका पाकर बदमाश तूफान लेकर हवा हो गए। बाइक जप्त करने बाद पुलिस व विद्यालय के संचालक की टीम अलग-अलग दिशा में गाड़ी को ढूंढने निकली लेकिन शातिर

बदमाशों ने किसी भी जगह टोल टैक्स पर गाड़ी को क्रॉस नही किया। जबकि सातरून्डा चौकी पर रतलाम जाती गाड़ी देखने बाद पुलिस व विद्यालय की टीम बिलपांक टोल टैक्स, बदनावर के बोराली टोल टैक्स, बिलपांक थाने के कैमरे, रोड़ किनारे लगी दुकानों के कैमरे, बिरमावल पुलिस चौकी, पेट्रोल पम्प आदी जगह के फुटेज खंगाले पर पुलिस को कौ सफलता नही मिली। उसके बाद भेसोला चौपाटी पर तूफान सीसीटीवी कैमरे में दिखी उज़के बाद फिर पुलिस टीम व संचालक अक्षत वैष्णव ने पेटलावद रोड, करवड़, राजोद आदि जगह जगह-जगह फुटेज तलाशती रही। उसके बाद फिर पुलिस को लाबरिया में लगे कैमरे में गाड़ी दिखी तब से पुलिस सरदारपुर, राजगढ़, तिरला सहित कई जगह लगातार तूफान की तलाश में लगी हुई है। लेकिन 16 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस को भी समझ मे नही आ रहा कि आखिर बदमाश कहा गायब हो गए। पुलिस की मिली बाइक की नम्बर प्लेट को आधार बनाकर भी तलाश करी तो उक्त बाइक एरोड्रम पुलिस थाने की नीकली परन्तु पुलिस का उक्त बाइक मालिक से सम्पर्क नही हो सका और न ही उक्त बाइक की चोरी की कही भी रिपोर्ट दर्ज है।

आखिरकार मानसून ने बहादुर सागर तालाब के काम को अधूरा रोक ही दिया, नपा हो गई सफल...?

अधर में लटक गई नगरपालिका की तालाब से जुड़ी कई कार्य योजनाएं

आने वाले वर्ष में फिर नपा द्वारा दोही जाएगी तालाब रूपी दुधारू गाय

माही की गूंज, झाबुआ।

कहते है समय पर किया गया कार्य ही सार्थक होता है, समय निकल जाने के बाद कार्य की सार्थकता लगभग समाप्त हो जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है झाबुआ शहर के बहादुर सागर तालाब के साथ। नगरपालिका ने इस तालाब को सुंदर व स्वच्छ बनाने के लिए अमृत योजना 2 में 1 करोड़ 6 लाख रूपये की राशि से जैव विविधता संरक्षण का काम शुरू किया था। इस काम के लिए नगरपालिका के पास पर्याप्त समय भी था, मगर अफसोस कि नगरपालिका ने इस समय की कदर नहीं की। नतीजा यह हुआ कि, बहादुर सागर तालाब का काम समय रहते पूरा नहीं हो सका और मानसून ने जिले में अपनी दस्तक दे दी। अब बहादुर सागर तालाब का यह कार्य अधर में चला गया है। इस काम को पूरा करने के लिए अब फिर से सालभर का इंतजार करना पड़ेगा।

पूर्व में हुए तालाब सौंदर्यीकरण के नाम पर घोटालों के बाद आमजन को यह महसूस हुआ था कि, अमृत योजना 2 में कम से कम बहादुर सागर तालाब की बदतर स्थितियों में परिवर्तन आएगा लेकिन नगरपालिका के निकम्मों ने इसे भी अब अधर में लटका दिया है। कहने को तो नगरपालिका व ठेकेदार ने फरवरी माह से हजारों जल प्राणियों की हत्या कर इस तालाब के कार्य को प्रारंभ कर दिया था। फरवरी से शुरू हुए इस कार्य की गति व गुणवत्ता पर लगातार मीडिया ने सवाल भी उठाए थे। मगर मीडिया के तमाम प्रयासों और अखबारों में छपि खबरों का न तो नगरपालिका के निकम्मों पर कोई असर हुआ और ना ही ठेकेदार पर। नतीजा यह हुआ कि, मानसून की दस्तक के साथ ही तालाब का काम अधर में लटक चुका है। तालाब में पानी की आवक शुरू हो चुकी है और देखते ही देखते यह पानी से पूरा भर जाएगा। नगर की जनता का बहादुर सागर तालाब को सुंदर दशा में देखने का सपना मानसून के साथ ही दफन होता दिखाई दे रहा है।

तालाब के गहरीकरण का कार्य भी अधूरा ही रह गया है। मानूसन आने के साथ तालाब में पानी आ चुका है और अब आगे इसका गहरीकरण का कार्य हो ही नहीं सकता। इसलिए जो काम अधूरा है वह अब आने वाले ग्रीष्म काल तक अधूरा ही रहेगा। हालांकि नगरपालिका के जिम्मेदारों ने मीडिया को कई तरह के वक्तव्य दिए जिनमें तालाब के कार्य को लगभग पूर्ण बताया गया। मगर जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। अतिक्रमण किए गए तालाब के हिस्से को अतिक्रमण मुक्त ना करवाते हुए यथा स्थिति में इस तालाब में पीचिंग कर दी गई।

हांलाकि जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो तहसीलदार ने अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस जारी किए। इसमें एक अतिक्रमणकर्ता के रूप में खुद नगरपालिका को भी नोटिस पहुंचाया गया। मगर जब तक अतिक्रमणकर्ताओं के पास यह नोटिस पहुंचे तब तक मानसून सर पर आ खड़ा हुआ था और अतिक्रमणकर्ताओं के जवाब देने के पहले ही मानसून धमक गया। अब यह तो तहसीलदार ही जाने की वे इन अतिक्रमणकर्ताओं पर आगे किस तरह की कार्रवाई करेंगे। क्योंकि अब तो तालाब में हुए अतिक्रमण तक पहुंचना भी लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। तालाब में पानी भर जाने के बाद कोई स्थिति ऐसी नहीं बनती की अतिक्रमण को हटाया जा सके। हां मगर जो अतिक्रमण सड़क के रास्ते पहुंच में है वे जरूर हटाए जा सकते है लेकिन वह भी इतना आसान तो नहीं होने वाला है। मतलब स्थिति यहां भी अधर में लटकने वाली ही दिखाई पड़ रही है।

इसके अलावा पिछले दिनों में नगरपालिका अध्यक्ष के जो वक्तव्य सामने आए थे, वह भी मानसून की आमद से हवा हवाई होते नजर आ रहे है। नगरपालिका अध्यक्ष ने अपने बयान में कहा था कि, बहादुर सागर तालाब में अधूरे कामों को तेजी से पूरा किया जाएगा। इसके अलावा तालाब के बीच बने टापू नुमा टीले को भी 70 प्रतिशत तक कम किया जाएगा। मगर नगरपालिका अध्यक्ष के इस दावे की मानसून ने हवा निकालकर रख दी है। क्योंकि जिस टापू को काटकर छोटा करने की बात नगरपालिका अध्यक्ष कर रही थी वह अब जलमग्न हो चुका है और उसके चारों ओर पानी भर चुका है। यह स्पष्ट है कि अब यह कार्य इस वर्ष तो नहीं हो सकता। हालांकि आश्चर्य की बात तो यह है कि, नगरपालिका अध्यक्ष ने जब यह बयान दिए थे जब मानसून महज कुछ ही दिन दूर था। तो यह सोचा जा सकता है कि, नगरपालिका अध्यक्ष का यह बयान झूठ का पुलिंदा ही साबित हुआ है। क्योंकि यह तो वह भी जानती थी कि कुछ ही समय में मानसून दस्तक देने वाला है और जिन कामों को करवाने के लिए वे बयान दे रही है वह इस वर्ष तो पूरे होना संभव नहीं है। मतलब सफेद झूठ!

बहादुर सागर तालाब में टीले को छोटा करने की बात को अगर छोड़ भी दिया जाए तब भी तालाब में इतना काम बाकी है कि, अगर मानसून कुछ दिन और भी लेट हो जाता तब भी यह काम पूरा होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही थी। तालाब के जो घाट वर्तमान में बचे हुए है जिन पर अतिक्रमण नहीं हुआ है, उनका जिर्णोद्धार का कार्य भी पूर्ण तरीके से अधूरा है। छतरी घाट, नसिया जी से लेकर व्यायामशाला तक के किनारों की दीवार पर भी किसी तरह का कोई कार्य नहीं हो पाया है। जबकि इन दिवारों पर प्लास्टर कर इनका जीर्णोद्धार किया जाना था। व्यायाम शाला के किनारे की तरफ पिछले वर्ष बारिश में धंसी हुई दीवार बनाई जाना थी, लेकिन इस दीवार का कार्य भी कछुआ गत से चला और अब तक अधूरा है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि, यह कार्य भी इस वर्ष पूरा हो सकेगा। हालांकि इस दीवार को पूरा करने में ठेकेदार तालाब में पानी आने के बाद भी मशक्कत करता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सफलता मिलना मुश्किल ही दिखाई पड़ रही है। क्योंकि जैसे ही तालाब में जल स्तर बढ़ेगा वैसे ही ठेकेदार को यह काम भी बंद करना ही पड़ेगा।

कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि, नगरपालिका इस वर्ष पर्याप्त समय होने के बावजूद बहादुर सागर तालाब का कार्य पूर्ण नहीं कर सकी। जबकि तमाम मीडिया ने इस कार्य को लेकर संजीदगी से आने वाली समस्याओं, काम की गति व हो रही अनियमितताओं को जनता के बीच रखा। बावजूद इसके नगरपालिका व ठेकेदार ने इससे कोई सबक नहीं लिया। एक तरह से यह लगता था कि शायद नगरपालिका इस कार्य को पूर्ण करना ही नहीं चाहती और शायद इस काम में वह सफल भी हो गई।

अब वह बात सत्य साबित होती नजर आ रही है कि, शहर के तालाब नगरपालिका के लिए दुधारू गाय बन चुके है। हर बार की तरह आने वाले वर्ष में फिर से यही कहानी दोहराई जाएगी। तालाब सौंदर्यीकरण के नाम से फिर से राशि स्वीकृत करवाई जाएगी और जिस तरह पूर्व में होता आया है भष्टाचार की गंगा में फिर से डूबकी लगाई जाएगी।

कारखानों की ज़हरीली बदबू से क्षेत्र के लोगों का घुट रहा दम, ज़हरीली हवा से जीना भी हुआ मुश्किल

कुत्तों की मौत पर कार्रवाई करने वाला प्रशासन इंसानों को धीमा जहर देने वालों पर मौन

माही की गूंज, मेघनगर। इमरान शैख

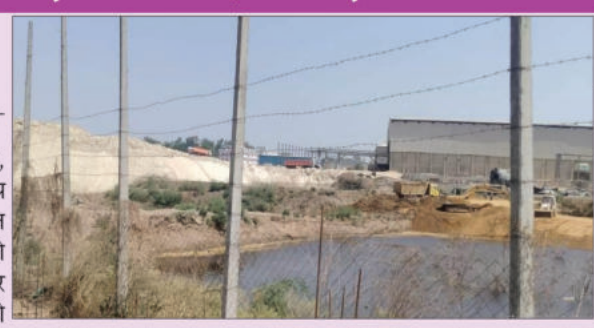

औद्योगिक क्षेत्र में लगे केमिकल, टायर, रोक फास्फेट, खाद सहित अन्य कारखानों ने मानव जीवन के मूल आधार, जल के समस्त स्त्रोतो को जहरीले केमकलों से इतना दूषित कर दिया की पानी का रंग बदलकर लाल हो गया। जिससे इलाके के कई लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो गए। इस ज़हर के खिलाफ कई सामाजिक संगठनों, आम लोगों, राजनीतिक दलों सभी ने विरोध किए, बड़े बड़े आंदोलन किए लेकिन इन ज़हर फेलाने वाले उद्योगों पर व उद्योग माफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने आज तक कोई ठोस कार्रवाई नही की। कहते हैं कानून से बड़ा कोई नही होता मगर मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र में संचालित कारखाने जिनमें 100 प्रतिशत कारखाने पर्यावरण संरक्षण कानून 1986, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) कानून 1974, वायु (प्रदूषण की रोकथाम) 1981 इन सभी कानूनों में से किसी भी शर्तों पर खरे नहीं उतरते तथा इन कानूनों के परिपालन में मिलने वाला अनापत्ति प्रमाण पत्र भी सभी उद्योगों को फर्जी तरीके से आवंटित किए गए हैं। लेकिन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों की आर्थिक सांठगांठ से इन उद्योग माफियाओं का जहर का यह कारोबार दिन ब दिन मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ता ही जा रहा है, व जिन टायर प्लांट को गुजरात हाई कोर्ट ने प्रतिबंधित कर दिए उनको भी यहां स्थापित करवा दिए। मतलब प्रशासन का दोहरा चेहरा देखिए जिस जहर को आप गुजरात में नही बना सकते, जिसका कारखाना स्थापित नही कर सकते उसे मध्यप्रदेश में बेखौफ बना सकते हो, स्थापित कर सकते हो। गुजरात में जिसे जहर माना गया उसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की साठगांठ से मेघनगर में वो उद्योग अमृत हो गया।

सांस में जहर, जीना भी हुआ मुश्किल

पहले तो उद्योगों ने क्षेत्र का सारा जल दूषित कर दिया, तो शहरी लोगो ने जैसे-तैसे आर ओ का पानी खरीद कर खाने और पीने में इस्तेमाल करना शुरू किया। मगर ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासी अब भी वही हैंडपंप और जलशायों और ज़हरीले केमिकलों का दूषित जल पीने को मजबूर है और कई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इन केमिकलों से आदिवासी समाज के जीवन यापन का मुख्य स्त्रोत उनकी खेती की सारी जमीने ही बंजर हो गई और तो और अब तो इन कारखानों से दिन और रात निकलने वाली जहरीली बदबू से सारे क्षेत्र के लोगों का दम घुटने लगा है, लोग उल्टियां करने लगे हैं, मगर प्रशासन अपनी कुंभकरणीय नींद से जागने को तैयार ही नहीं है। इन चंद रसूखदार उद्योग माफियाओं को बचाने के लिए लोकतंत्र की असली मालिक जनता की जान से खिलवाड़ करने से भी नही हिचक रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हो रहा उल्लंघन

इन उद्योगों से निकलने वाला दूषित जल और केमिकलों ने वायु को भी पूर्ण प्रदूषित कर दिया है, जो सीधे-सीधे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए लोगों के स्वस्थ जीवन जीने के मौलिक अधिकार का हनन तो है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सुनील बत्रा बनाम दिल्ली सरकार में दिए गए उस आदेश को भी खुली अवमानना है जिसमें उसने स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया था। लेकिन प्रशासन संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के परिपालन में जनता के अधिकारों और स्वास्थ्य का सरंक्षण करने की बजाए इन जहर फैला रहें रसूखदार उद्योग माफियाओं को सरंक्षण देने में लग जाता है और छोटी मछलियों को नोटिस, कुछ समय के लिए कारखाने बंद करने की नौटंकी कर रस्म अदायगी कर इतीश्री कर लेता है। लेकिन हवा, पानी में जहर फैला रहे इन उद्योगों और उनके मालिकों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नही करता है।

प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा क्यो नही किया जा रहा अधिकारो का पालन

जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण कानून, भारतीय दंड विधान तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 में स्थानीय प्रशासन और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण करने वाली इकाइयों को स्थाई तौर पर बंद करने और उनके मालिकों के विरुद्ध मानव जीवन को खतरे में डालने के लिए कई गंभीर धाराओं में अपराधिक करवाई करने के अधिकार प्रदत है। मगर कई बार आर्थिक सांठगांठ से, तो कई बार राजनितिक रसूख के चलते इन जहर फेलाने वाले उद्योगों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नही होती और जनता जहर वाला पानी पीने और दम घुट-घुट कर जीने को मजबूर है। प्रशासन की ये लापरवाही और जनता का सब्र किसी दिन ज्वालामुखी बनकर फुट गया तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन ही होगा।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से ही जनता को उम्मीद

अब तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को चाहिए की वो अपनी टीम भेजकर मेघनगर आद्योगिक क्षेत्र के इन समस्त उद्योगों की जांच करवाए जिसमें समस्त उद्योगों को मिले अनापत्ति प्रमाण पत्र की जांच, क्षेत्र के जल के नमूने संरक्षित कर उनकी जांच करे साथ ही इस क्षेत्र के वायु सूचकांक की भी जांच करे और उन समस्त उद्योगों को स्थाई तौर पर बंद कर दे जो क्षेत्र के जल और वायु में जहर घोल कर लोगों का जीना मुहाल किए हुए है।

श्वान हत्याकांड की आड़ में कही भूमिका सोनी को ओछी राजनीति का शिकार बनाने का तो नही है प्लान!

घटनाक्रम में लगातार घेरा जा रहा है भाजपा महिला जिलाध्यक्ष भूमिका सोनी को

माही की गूंज, झाबुआ।

वैसे तो हमारे देश में जीव दया को लेकर बहुत सी संस्थाएं काम कर रही है, लेकिन इन्हे जमीनी स्तर पर कभी सड़कों पर मुक पशुओं के लिए काम करता नहीं देखा गया। हां इतना जरूर है कि, जब भी कोई मुक पशु किसी घटना का शिकार होता है और उसके पीछे किसी इंसान का नाम जुड़ जाता है, तब यही संस्थाएं पाताल से निकल आती है और इतना हंगामा करती है कि, जैसे जो मुक पशु मरा है उसकी प्रजाति विलुप्ति की कगार पर हो और जिस इंसान का नाम घटनाक्रम से जुड़ता है वह जीव हत्यारा ना होकर किसी इंसान का हत्यारा हो। वैसे इस देश में मानव हत्या के बावजूद लोगों को जमानत या रीहाई मिल जाती है। मगर एक पशु की हत्या पर जीव दया पर काम करने वाली संस्थाएं, सोशल एक्टिविस्ट, एनिमल राइट एक्टिविस्ट मीडिया की सुर्खियां समेटने इतना उतैजित हो जाती कि, जीव हत्या करने वाले को कोर्ट-कचहरी और जेल भिजवाने के साथ कठोर दंडात्मक कार्यवाही की धौंस दपट देकर डराने और धमकाने लगते है।

ऐसा ही एक मामला जिले के थांदला नगर में सामने आया है। कहने को तो यहां नगरपरिषद के कुछ कर्मचारियों ने दो कुत्तों को लाठी से पीट-पीटकर मार डाला। उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो गई और उन्हे निलंबित भी कर दिया गया। मगर बात यहां शांत नहीं हुई और एक पार्षद को खुले रूप से टारगेट किया गया। नकली जीव दया प्रेमियों व सोशल एक्टिविस्ट, एनिमल राइट एक्टिविस्ट ने यह मांग उठाई की पार्षद के कहने पर कर्मचारियों ने श्वानों की हत्या की है, तो पार्षद पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पार्षद पर कार्रवाई को लेकर इतना बड़ा बखैड़ा खड़ा किया गया कि, अब यह स्पष्ट नजर आता है कि एक महिला पार्षद ओछी राजनीति का शिकार होती दिखाई दे रही है।

श्वान की मौतों को लेकर जो मामला दिखाई दे रहा है वह शायद इतना बड़ा भी नहीं था, लेकिन इस पूरे मामले में पर्दे के पीछे जो कहानी गढ़ी जा रही है, उससे राजनीतिक षड़यंत्र की बू आ रही है। वरना ऐसा क्या हो गया था जो महज श्वान की मौत को लेकर जिले में इतना बड़ा बवाल हो गया। न जाने कहां-कहां से सोशल एक्टिविस्ट, एनिमल राइट एक्टिविस्ट, जीव दया को लेकर काम कर रही संस्थाओं के मुखियाओं ने महिला पार्षद को फोन कर इतना धौंस-दपट कर डाली की मानों उन्होने किसी इंसान की हत्या कर दी हो। इन सोशल एक्टिविस्ट, एनिमल राइट एक्टिविस्ट और जीव दया प्रेमियों का प्रेम इतना उमड़ा कि उन्होने महिला पार्षद को कोर्ट-कचहरी में घसीटने तक की धमकियां दे डाली।

जिस तरह का प्रेम थांदला के कुत्तों के लिए इन सोशल एक्टिविस्ट, एनिमल राइट एक्टिविस्ट, जीव दया प्रेमियों का देखने को मिल रहा है, वह शायद हर कुत्ते के नसीब में नहीं है। वरना जिले से गुजर रहे तमाम नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे पर हर दस-पन्द्रह किलोमीटर की दूरी पर एक न एक श्वान के चिथड़े सड़कों पर बिखरे देखने को मिलते। जी हां हालात तो ऐसे है कि जिले के किसी भी हाईवे पर निकल जाईये हर सड़क पर किसी ना किसी श्वान का शव छत-विच्छत पड़ा मिल ही जाएगा। तमाम सोशल वर्करों और एनिमल राइट एक्टिविस्ट लोगों को जरूरत तो इस बात की है कि वे बस एक बार इन हाईवे पर निकलकर तो देखें। मगर हम जानते है कि ऐसा कोई करने वाला नहीं है। यह भी हो सकता है कि यह लोग हाईवे पर सफर करते होंगे और इन्हे भी यह सब दिखाई तो देता ही होगा, मगर एक भी सोशलिस्ट या एनिमल राइट एक्टिविस्ट यह जहमत बिल्कुल नहीं करता कि श्वानों के छत-विच्छत शवों को रास्ते से हटाकर एक तरफ रख दे। कभी ऐसी कोई खबर भी मीडिया के जरिए देखने को नहीं मिलती कि किसी सोशलिस्ट या एनिमल राइट एक्टिविस्ट ने रास्ते में पड़े घायल श्वानों या उनके शवों को उठाया हो या रूक कर उपचार दिया हो।

मगर थांदला नगर में एक श्वान हत्याकांड ने इतना बवाल मचा दिया कि सारे सोशल एक्टिविस्ट और एनिमल राइट एक्टिविस्ट पाताल से निकल कर आ गए और एक महिला पार्षद जो कि भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष भी है को घेरने लगे। सारा घटनाक्रम तो इसी तरफ इशारा करता है कि, भूमिका सोनी को ओछी राजनीति कर घेरने का प्रयास किया जा रहा है। हम यहां किसी का पक्ष नहीं ले रहे है, लेकिन अगर जीव दया है तो फिर वह सारे जानवरों के लिए होनी चाहिए। नगर में घूम रहे जानवरों के लिए ही नहीं वरन हाईवे पर मौत का शिकार हो रहे जानवरों के लिए भी होनी चाहिए।

इसे अगर राजनीतिक चश्में से देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर इस पूरे मामले में राजनीति किस गिरे हुए स्तर की हो रही है। पहला तो यह कि भूमिका सोनी एक चुनी हुई पार्षद के साथ भाजपा महिला मोर्चे की जिलाध्यक्ष भी है। वे पिछले दो बार से पार्षद का चुनाव लड़ रही है। पिछली बार भी भूमिका अपने ही समाज के एक बंटाधार परिवार जो भाजपा में अपनी पैठ रखता है के सामने चुनाव लड़ी थी। इस बार भी भूमिका ने भाजपा से चुनाव लड़ने का मन बनाया था, लेकिन बंटाधर कंपनी ने उसे भाजपा से टिकट नहीं मिलने दिया। भूमिका ने साहस दिखाया और बंटाधार कंपनी के भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय मैदान में उतरी। नतीजा यह रहा कि बंटाधार कंपनी का भाजपा प्रत्याशी भूमिका के सामने धराशाई हो गया और भूमिका पार्षद का चुनाव जीत गई। अब इत्तेफाक यह कि दोनों ही परिवार सोनी, दोनों ही परिवार के बीच राजनीतिक द्वेषता और सोने पर सुहागा यह कि भूमिका निर्दलीय होकर पार्षद का चुनाव जीत गई। अब यह द्वेषता अपने चरम पर है।

लोग बताते है कि, भूमिका को घेरने के लिए बंटाधार कंपनी लगातार पीछे पड़ी हुई थी और जैसे ही श्वान हत्याकांड हुआ वैसे ही बंटाधार कंपनी ने येन-केन प्रकारेण यह मामला भूमिका के माथे मढ़ने की प्लानिंग बना ली। भूमिका के कथन अनुसार उसने सिर्फ नगरपालिका में आवारा घूम रहे श्वानों को पकड़कर उन्हे नगर से बाहर छोड़ने की मौखिक शिकायत की थी। नगरपरिषद के किस अधिकारी ने कर्मचारियों को आदेश दिए कि वे श्वानों की हत्या कर दे। जबकि जिम्मेदारों के बयान है कि, कर्मचारियों को श्वानों को पकड़ने के लिए भेजा गया था न की मार डालने के लिए। अब कर्मचारियों पर तो कार्रवाई हो चुकी है। मगर अब भी कुछ सोशलिस्ट और एनिमल राइट एक्टिविस्ट लगातार इस बात की मांग कर रहे है कि, भूमिका पर कठोर कार्रवाई की जाए। हालांकि यह संभव नहीं है, क्योंकि भूमिका का श्वानों की मौत से डायरेक्ट या इन डायरेक्ट कोई कनेक्शन ही नहीं है। ना भूमिका किसी वीडियो में दिखाई दे रही है और ना ही भूमिका ने लिखित में कोई शिकायत नगरपालिका को की है। जो भी मामला चल रहा है वह सिर्फ मौखिक और औपचारिक तौर पर ही चल रहा है। जिससे यह साबित हो रहा है कि भूमिका को पूरी तरह से राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है।

बताने वाले बताते है कि, बंटाधार कंपनी का अब एक ही लक्ष्य रह गया है कि, भूमिका को इतना बदनाम किया जाए कि उसका पद और प्रतिष्ठा दोनों ही खत्म हो जाए। हालांकि बंटाधार कंपनी पर्दे के पीछे रहकर काम कर रही है, लेकिन यह तो जग जाहिर है कि, थांदला नगर में सोनी बनाम सोनी तो है ही। भले ही बंदूक किसी और के कंधे पर रख कर चलाई जा रही हो, मगर शिकार और शिकारी दोनों को ही जनता भली-भाती जानती है। वरना यह कैसे संभव है कि, देश के बड़े-बड़े सोशल वर्करस्, एनिमल राइट एक्टिविस्ट और जीव दया प्रेमियों को छोटे से शहर थांदला में घटी एक घटना की खबर इस तरह से लग जाए और वे सारे लोग एक सुर में सिर्फ भूमिका पर कार्रवाई करने की मांग करने लगे। यहां तक की भूमिका को कोर्ट-कचहरी में घसीटने की धौंस दे डाले। यह सारा घटनाक्रम जैसे प्रायोजित नजर आता है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422